www.ghoonghatkibagawat www.ghoonghatkibagawat ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 27 गोरखपुर, 12 जनवरी 2025 रविवार पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की आर्द्रभूमियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया

शीर्ष अदालत के निर्देश के लगभग एक महीने बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने वकील जनक द्वारकादास को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। उन मुद्दों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत नोट दाखिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्णय लेने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने केंद्र, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, राज्य पर्यावरण, वन और राजस्व मंत्रालयों के साथ-साथ महाराष्ट्र वेटलैंड्स प्राधिकरण को भी नोटिस जारी किया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में वेटलैंड्स के संरक्षण का मुद्दा अपने आप उठाया और भारत में 2.31 लाख से अधिक वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देश की निगरानी के लिए एक कानूनी सलाहकार नियुक्त किया। दिसंबर, 2024 को, शीर्ष अदालत ने 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र-फल वाले सभी आर्द्रभूमियों का सीमांकन करने के लिए भारत भर के राज्य आर्द्रभूमि अधिकारियों को तीन महीने की समय सीमा दी। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद, इन आर्द्रभूमियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित उच्च न्यायालयों को इस मुद्दे की निगरानी करने के लिए भी कहा था।

शीर्ष अदालत के निर्देश के लगभग एक महीने बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने वकील जनक द्वारकादास को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। उन मुद्दों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत नोट दाखिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निर्णय लेने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने केंद्र, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, राज्य पर्यावरण, वन और राजस्व मंत्रालयों के साथ-साथ महाराष्ट्र वेटलैंड्स प्राधिकरण को भी नोटिस जारी किया।

शीर्ष अदालत ने अपने निर्देश में कहा था कि 2017 से पहले, भारत में 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली आर्द्रभूमि की संख्या के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा दिए गए आंकड़े 2,01,503 थे। शीर्ष अदालत ने 2021 में प्रकाशित नवीनतम इसरो डेटा का हवाला देते हुए दिखाया कि यह आंकड़ा अब 2,31,195 हो गया है।

बाल पोर्नोग्राफी गंभीर अपराध

भारतीय न्याय संहिता, 2023 एक ऐतिहासिक पहल है जिसे भारतीय दंड साहिता, 186 को बदलने के लिए लाया गया है। यह संहिता भारतीय न्याय प्रणालीमें व्यापक बदलाव लाने का वादा करती है लेकिन क्या यह वास्तव में न्याय प्रणाली में क्रांति ला पाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए राजद्रोह का अपराध परिभाषित करती थी । यह धारा उन लोगों को दंडित करती थी जो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष फैलाने का प्रयास करते थे। इस कानून के आलोचकों का मानना था कि इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता था। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। संहिता ने राजद्रोह के अपराधको निरस्त कर द्विया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम हैं। भारतीय न्याय संहिता ने राजद्रोहके अपराध को हटाकर उसके स्थान पर अपराधों को परिभाषित किया है। ये नए अपराध देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संब्राधित हैं । इनमें शामिल हैं लोगो के बीच फूट डालने का प्रयास, सशस्त्र विद्रोह या हिंसा को भड़काना, अलगाववादी गतिविधियां, राजद्रोह कानून के निरसन को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि इस नए कानून का दुरुपयोग न हो। संहिता ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को कड़ा कर दिया है। इसमें बलात्कार, यौन उत्पड़न और घरेलू हिंसा शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता,2023में बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा बढ़ा दी गई है। साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियों में बलात्कार के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। यौन उत्पीड़न को गम्भीर अपराध माना गया है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। अब घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित महिलाओं को अधिक सुरक्ष प्रदान की जाएगी। छेडछाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है शादी के वादे के झांसे में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने पर अब तीन साल तकं की जेल की सजा हो सकती है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ये बदलाव महिलाओं को न्याय दिलाने, सशक्त बनाने और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने में मदद करेंगे और अपराषियों को कठोर सजा दिलाएंगे। संहिता ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई नए प्रावधान जोड़े हैं। बाल यौन शोषण के मामलों में अधिकतम सजा बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त बाल पोर्नोग्राफी को एक गम्भीर अपराध माना गया है। बाल तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। बाल तस्करों को कठोर सजा दी जायगी। बाल और बाल विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। भारतमें बाल अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह संहिता बच्चों को अपराध और बच्चों को शोषण से बचाने में मदद करेगी। संहिता में साइबर अपराधों से निबटने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं । बीएनएस ने साइबर अपराधों की परिभाषा को विस्तृत किया है, जिसमें हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर उंत्पीड़न और अन्य प्रकार के साइबर अपराध शामिल हैं यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रकार के साइबर अपरारधों को कानून के दायरे में लाया जा सके। बीएनएस ने साइबर अपराधों के लिए कड़े दंडका प्रावधान किया है।

संहिता ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई नए प्रावधान जोड़े हैं। बाल यौन शोषण के मामलों में अधिकतम सजा बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त बाल पोर्नोग्राफी को एक गम्भीर अपराध माना गया है। बाल तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। बाल तस्करों को कठोर सजा दी जायगी। बाल और बाल विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। भारतमें बाल अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह संहिता बच्चों को अपराध और बच्चों को शोषण से बचाने में मदद करेगी।

बांग्लादेशी महिलाओं के साथ पाकसेना की बर्बरता

कातिल की ये दलील भी मुसिफ ने मान ली, मक्तूल खुद गिरा था खंजर की नौक पे'। बंगलादेश की मौजूदा हुकूमत के सामने वहां के अल्पसंख्यक समुदायपर हो रहा तशद्दुद एवं हिंसाका खौफनाक मंजर कुछ यही बयान कर रहा है जाहिर है जब कातिल खुद ही अदालत का मुंसिफ होगा तो उसके एब-ओ-हुनर की तफ्तीश नहीं हो सकती। पाकिस्तानी सैन्य हुक्मरानों के जहन में बंगला लोगों के प्रति नफरत एवं हिकारत इस कदर थी कि पाकिस्तानी जरनैल 'अयूब खान' ने अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में तख्तापलट का पहला मजमून लिखकर बंगाली मूल के राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा को बर्खास्त करके पाकिस्तान छोड़ने का फरमान जारी कर दिया था। बर्तानिया में शरण लेने के बाद 12 नवंबर 1969 को लंदन में फौत हुए 'इस्कंदर अली मिर्जा' की मय्यत को पाकिस्तान में दफनाने की इजाजत भी नहीं मिली। काफी जद्दोजहद के बाद साबिक सदे पाकिस्तानी इस्कंदर मिर्जा के ताबूत को पड़ोसी मुल्क 'ईरान' में कब्र नसीब हुई थी। अपनी आजादी के प्रति भी बंगलादेशियों के दोहरे मापदंड थे। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का शिकार हुए पूर्वी पाकिस्तान के सियासी रहनुमा भारतीय सेना के रहमोकरम से आजाद होकर अपना बंगला निजाम नाफिज करना चाहते थे। परन्तु बंगलादेशकी कुछ सियासी जमातें एवं मजहबी रहनुमां आजाद होकर मानसिक एवं जज्बाती तौरपर पाकिस्तानके साथ ही रहना चाहते थे । मार्च 1971 में बंगला आवामपर पाकिस्तानी सेना की दरिन्दगी के बदनुमा दाग बंगलादेश में आज भी मौजूद हैं। बंगलादेश की महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेनाने जो बर्बरताका सलूक किया था। उस शर्मनाक कारकर्दगी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी सेना की हलाकत से बचने के लिए लाखों बंगला लोगों ने हिजरत करके भारत के सरहदी राज्यों में शरण ली थी। इन्सानियत का कत्ल तब होता है, जब पीड़ित को उठाने के बजाय लोग तमाशा देखने लगे। सन् 1971 में भी यहीं हुआ । पूर्वी पाकिस्तानको कत्लोगारत का मुद्दा भारत ने कई मुल्कों के समक्ष उठाया। लेकिन बंगला लोगों की पाकिस्तान के जुल्मोसितम से बचाने एवं शरण देने की जहमत किसी भी मुल्क ने नहीं उठाई। जगजाहिर है कि भारतीय सेना के जोरदार पलटवार बेबस होकर पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को नए मुल्क बंगलादेश में तब्दील कर दिया था परन्तु बंगलादेश के मजहबी रहनुमां अपनी आजादी का श्रेय भारतके बजाय अपनी मुक्ति वाहिनी को दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मुक्ति वाहिनी को हथियार उपलब्ध कराकर भारतीय सेना ने ही प्रशिक्षित किया था। बंगलादेश की चरमपंथी जमातें एवं मजहबी रहनुमां पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अलबत्ता यहां अगरतला षड्यंत्र का जिक्र करना जरूरी है। बंगलादेश की सत्ता से बेदखल होकर भारतमें शरण ले चुकी साबिक वजीरे आजम शेख हसीनाके वालिद शेख मुजीबुर्रमान को अगरतला षड्यंत्र का हवाला देकर पाकिस्तानी सेना ने मई 1968 में कैद कर लिया था। पाक सदर अयूब खान के दौरे हुकूमत में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किउए गए कई बंगला नागरिकों एवं पाकिस्तानी नौसेना के बंगाली मूल के अधिकारियों पर इल्जाम था कि उन लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला में हिंदोस्तान से समर्थन की गुजारिश की थी। अगरतला साजिश को पाकिस्तानी हुकुमत ने पूर्वी पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरनाक चुनौती माना था। अगरतला षड्यंत्र को बेनकाब करने का खुलासा पूर्वी में तैनात आईएसआई के कर्नल शम्सुल आलमने किया था।

शम्सुल आलम को पाकिस्तानी सैना ने शांतिकाल के सर्वोच्च पदक सितारा-ए-बसालत से सरफराज किया था। हालांकि अदालतमें शेख मुजीब पर अगरतला षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान को अस्थिर करने का आरोप साबित नहीं हुआ था, परन्तु पाकिस्तानी सेना ने 15 फरवरी 1969 को अगरतला साजिश के आरोपी बंगला सार्जेंट जहूरूल हक को जेल में ही हलाक कर दिया था। जहूरूल हक के कत्ल की खबर से पूर्वी पाकिस्तान भयंकर हिंसा की चपेटमें आ गया। नतीजतन भारत की दखलंदाजी के खौफ से अयूब खान ने अगरतला षड्यंत्र का केस रद कर दिया। ढाका विश्वविद्यालय का एक हॉस्टल उसी जहूरूल हक के नाम से जाना जाता है परन्तु बंगलादेश के हुक्मरान तथा मजहबी रहनुमां पाकिस्तान को जिहादी उल्फत में इस कदर नाबिना हो चुके हैं कि सन् 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई कत्लोगारत को नजरअंदाज कर रहे हैं।

सूरतेहाल यह है कि बंगलादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की तमाम निशानियों को मिटाया जा रहा है। बंगला मुक्ति संग्राम में युद्धघोष बना जॉय बंगला नारेको भी हटाया जा रहा है। अविभाजित भारतमें सन् 1922 में बंगला शायर काजी नजरूल द्वारा अपनी नज्म में लिखा गया जॉय बंगला बंगलादेश का कौमी नारा है। सन् 1975 में जब बंगलादेश की सेना ने शेख मुजीबुर्रहमान का कत्ल किया तो उस वक्त जर्मन संघीय चांसलर विली ग्रांट ने जज्बाती अंदाज में कहा था कि मुजीब को हलाक करने वाले कोई भी जघन्य कार्य कर सकते हैं। अतः बंगलादेश के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल बंगलादेश की आजादी के लिए भारत के शूरवीरों ने मैदान-ए-हर्ब को अपने कल्ब-ए-लहू से सींच कर पाकिस्तान को तकसीम कर दिया। भारतीय सेना दखलअंदाजी न करती तो पाकिस्तान के राजपूत जरनैल टिका खान एवं राव फरमान अली का बंगलादेश में नरसंहार जिसका कोड बंगला हरियालीको लाल कर देंगे था. वह मुकम्मल हो जाता। काश ! मौहम्मद अली जिना एवं इस्कंदर अली मिर्जा भी पाकिस्तानकी तक-सीमको अपनी चश्म-ए-पलकसे देख पाते। अब प्रश्न उठ रहा है कि हजारों भारतीय सैनिकोंके बलिदानकी बुनियादपर वजूद में आए बंगलादेश को क्या बंगला हुक्मरानों को सौंपने का भारतका फैसला सही आ पाकिस्तान के कदमपर चलने वाले अहसान फरामोश बंगलादेशकी उसकी औकात दिखानी होगी।

अब प्रश्न उठ रहा है कि हजारों भारतीय सैनिकोंके बलिदानकी बुनियादपर वजूद में आए बंगलादेश को क्या बंगला हुक्मरानों को सौंपने का भारतका फैसला सही आ पाकिस्तान के कदमपर चलने वाले अहसान फरामोश बंगलादेशकी उसकी औकात दिखानी होगी।

परीक्षा के प्रति इतनी लापरवाही और उदासीनता क्यों?

शिक्षा में परीक्षाएं ही तय करती हैं कि बेहतर शिक्षा दी गई है या नहीं, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। परीक्षा के बिना शिक्षा दिशाहीन हो जाती है। वास्तविक शिक्षा का आकलन करने के लिए परीक्षा जरूरी है। परीक्षा से शिक्षकों को पता चलता है कि छात्रों ने विषयवस्तु पर किस स्तर तक महारत हासिल की है। शिक्षा का मूल्यांकन भी होता है। परीक्षा छात्रों में आत्म विश्वास बढ़ाती है क्योंकि परीक्षा में प्राप्त अंकों से छात्रों को भविष्य में और बेहतर करने के लिए हौसला बढ़ता है। छात्र दृढ़ता और लचीलेपन का मूल्य सीखते हैं। इससे छात्र विचारों को स्पष्ट रखने और समय का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। तात्पर्य यह कि शिक्षा के लिए परीक्षा का उतना ही महत्व है जितना चंदन के लिए पानी का और दिये के लिए बाती का। तो फिर परीक्षा के लिए इतनी लापरवाही और उदासीनता क्यों? यह तो वही बात हुई कि वर्षों की तपस्या के बाद वरदान प्राप्त करने का समय आया के आंखें लग गईं।

केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, शिक्षा को बेहतरी को लेकर तो जरूर बड़ी-बड़ी बातें की जाती है लेकिन परीक्षा आयोजित करने को लेकर नीति बनाई जाए। इसके लिए कहीं गंभीरता नहीं दिखती इसलिए बात राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षा एनईईटी (नीट) की करें, अथवा हाल में हुई बिहार लोकसेवा आयोग की परीक्षा या यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई हैं न तो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाएं इससे अछूती हैं और न राज्य स्तर पर होने वाली । मतलब, इस हमाम में सभी एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन बावजूद इसके कारगर परीक्षा नीति नहीं बन पाना निराशा जनक है।

गांव-देहात में कहावत खूब कही-सुनी जाती है- खाता न बही, हम जो कहें वही सही। - इस कहावत का निहितार्थ अलग हो सकता है लेकिन परीक्षाओं को लेकर देश और प्रदेशों में जो फिलहाल स्थिति यह है, उस पर सटीक बैठती है। परीक्षाओं को लेकर न तो केन्द्रीय स्तर पर कोई नीति बनाई गई है और नही राज्यों में परीक्षाओं के लिए बेहतर नीति-नियम है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने मन-मुताबिक परीक्षाओं को आयोजित करती हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि आएदिन पेपर लीक को घटनाएं सामने आती हैं, जिससे मेधावी छात्र-छात्राओं का मनोबल तो टूटता ही है सरकार की भी फजीहत होती है लेकिन, इन सबके बावजूद राष्ट्रीय या राज्यों के स्तर पर परीक्षा नीति बनाने की पहल नहीं की गई। विडम्बना है कि सरकार से लेकर सहकार तक सभी सिर्फ शिक्षा को हो बात करते हैं। परीक्षा की कोई बात नहीं होती है। जब कि शिक्षा के मूल में परीक्षा होती है। शिक्षा को परीक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।

परीक्षा तब सुर्खियों में जाती है जब पेपर लीक हो जाता है। नहीं तो शिक्षा और नौकरियों के बड़े-बड़े दावों के बीच परीक्षा की महत्ता और गुणवत्ता गुम हो जाती है जबकि सच तो यह है कि परीक्षा ही नौकरियों का प्रवेश द्वार है जब प्रवेश द्वार हो अराजकता और अनियमितता होगी तो प्रवेश के भीतर अपात्र लोगों को प्रवेश मिल जायेगा। जिसका असर न सिर्फ मेधा पर पड़ेगा अपितु राष्ट्र का भी बड़ा नुकसान होगा। जरूरी है कि परीक्षा के किए ऐसी कारगर नीति बने जिससे पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं करना घोड़ा खाए घास गधे को मिले च्यवनप्राश जैसी स्थिति हो जाती है / जाएगी। अर्थात अयोग्य लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी और योग्य लोग धूल फांकते रह जाएंगे। परीक्षा नीति बनाते समय ध्यान में रखना होगा कि शिक्षा या परीक्षा माफिया के लिए व्यवस्था में सेंधमारी-हो सके प्रश्न पत्रों का सुरक्षा कवच इतना मजबूत हो कि उसे भेदा न जा सके।

वन नेशन वन एक्जामिनेशन की चर्चा जोरों पर है। सरकार इसके अनेक लाभ भी बता रही है। ऐसे ही 2020 में वन नेशन वन एग्जामिनेशन की चर्चा खूब थी। इसी परिकल्पना के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का गठन किया गया था। लेतिन नीट-2024 में एनटीए की कितनी बदनामी हुई, बह किसी से छिपी नहीं है। इसोमेशा के साथ सरकार ने एक उम्मीद के साथ और एक प्रयास किया और 2020 में केन्द्रीय कैबिनेट से नेशनल रिक्टमेंट एजेंसी (एन आर ए) की मंजूरी दी गई थी। उम्मीद बनी थी कि परीक्षा के लिए कारगर नीति बनेगी और बार-बार परीक्षा देने से समय और पैसे को होने वालो बरबादी से निजात मिल जाएगी। लेकिन चार साल बाद भी नतीजा सिफर रहा एन आर ए को जिम्मा सोया गया था कि - वह गैर-तकनीकी पदों के लिए एस एस सी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग सर्विस पर्सनल की परोधा कराएगी। एन आरए के आगमन के बाद पूरी प्रक्रिया एकीकृत हो जाएगी जो छात्रों और एजेंसियों के लिए बोझिल प्रक्रिया को आसान बना देगा।

केन्द्र सरकार ने एक देश एक परीक्षा के तहत साल 2021 में पहला टेस्ट कराने का वादा किया था। लेकिन चार साल में 98 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अब तक कोई परीक्षा नहीं करायी जा सकी है।

सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है जिसके कारण उम्मीदवारों को अलग अलग एजेंसियों को अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए लम्बी दूरी भी तय करनी पड़ता है। इससे उनपर आर्थिक बोझ बढ़ता है।

रोटी खाने से कोई मोटा नहीं होता, घूस खाने से ...

यह दुनिया के सबसे युवा देश की दुखती रग है जिस पर अगर कभी साहित्य लेखन होगा तो वह बहुरंगी होगा। हरिशंकर परसाई ने तो लिखा ही है- बेइमानी के पैसे में ही पौष्टिक तत्व होते हैं। रोटी खाने से कोई मोटा नहीं होता, घूस खाने से होता है। आस पास ही देखने लगे तो इतने किरदार, शातिराना दिमाग बौद्धिक चोला पहने दिख जाएंगे जिनकी पहचान सरल स्वभाव वाला समाज तो नहीं कर पाता, उसका माथा तब ठनकता है जब उनके घर के बच्चे ठगे जाते हैं। बड़े खुलासे जो आज देखे पढ़े जा रहे हैं उनके बीज कैसे बोए जाते हैं इसके हम जैसे लाखों लोग साक्षी रहे होगे। कैसे छोटे-छोटे जाल में युवाओं को फंसाया जाता है, और कैसे बड़ी वसूली की जाती है। आदर्श की बातें सुनते-पढ़ते जो युवा, परीक्षा के पायदान से ही धांधली देख रहे हों, वो सिस्टम को भेदने के गुर धीरे-धीरे सीख लेते हैं। जो नहीं सीख पाते वे हाशिए पर ढकेल देने के बाद भी देश के असली कर्णधार बन कर निकलते हैं। चाहे कर्म की क्रांति से या सड़क के आंदोलनों से, सारा संघर्ष आदर्श की स्थापना के लिए हो रहा है। हमेशा। दोनों ही जगहों पर औपनिवेशिक कोख से जन्मी व्यवस्था उतनी ही बेशर्म है उतनी ही छद्म । पिछले पांच सालों में 19 राज्यों में करीब परीक्षाएं लीक हुई। एक सर्वे ने उस बात पर प्रकाश डाला है कि-ऑन लाइन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने माना कि उन्होंने चीटिंग की। वैसे यह बात बाज की नहीं है। स्वानुभवानुसार, भर्तियों और नौकरियों की प्रक्रियाएं हमेशा से दागदार रही हैं। मूल में तो लालच और नैतिकता का पतन हो है। विचारणीय है कि - ये सब कारगुजारी करने वाले लोग बड़े-बड़े पदों पर पहुंचते हैं। मंचों पर भी बुलाए जाते हैं । आदर्शवाद पर लम्बे चौड़े व्याख्यान भी इनके मुख से निकलते हैं। जो बड़े कमाल के होते हैं।

कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान जब परीक्षक आते थे तो विद्यार्थी उनकी जानकारी लेने की कवायद में लग जाते थे। कहां से हैं,कौन हैं और किनसे कहलवाया जा सकता है। इस तरह सो सवा सौ अंको के लिए बिकने वाले बिक जाते हैं। बात जरा सी लगती थी मगर थी तो बड़ी ही। विश्विद्यालय के विद्यार्थी जीवन में पत्रकारिता के ऐसे अध्यापक मिले जिन्होंने बिना पूंछे खुद ही बताया कि आपकी कॉपी कहां चैक होने गई है और मैं मिलवाने ले चलता हूं। हम तो जाने वाले नहीं थे। लेकिन ऐसे झांसे देने वालों को खूब मौज मस्ती करते देखा गया। जाने कितनों के नंबर बढ़वाकर कितनों की असल मेहनत पर पानी फेर दिया होगा इन्होंने । इसके बाद देश के बड़े संस्थान के लिए नामी पुस्तक लेखक भी टकरा गए जिन्होंने - पीएचडी थीसिस लिखने का प्रस्ताव रखा और उसकी कीमत भी बताई। हमारी जेब फूटी कौड़ी न थी, न दिमाग में ऐसी सोच थी। लेकिन इन घटनाक्रमों से इतना स्पष्ट था कि-यह तंत्र देखते-देखते उघड़ता चला गया। धीरे धीरे - समझ में आने लगी कि काम से काम रखने वाले लोग और भ्रष्ट का असहयोग करने वाले लोग हाशिए पर कैसे धकेल दिए जाते हैं। यह पूरी योजना काम कर रही होती है मगर सिर्फ उन्हें मन क लगती है जिन्हें फायदा उठा लेना चाहिए। होता है।

अध्यापन के क्षेत्र में पदार्पण करने के बाद भी कोई न कोई कांटा पांव मैं चुभता ही रहा है। राज्य के मुक्त विश्वविधालय से जब हमारे पास बिन कहे ही मूल्यांकन के लिए कापी आने से पूर्व हो उत्तीर्ण करने के लिए सिफारिशी फोन पर आने लगते। ऐसी स्थितियों में परीक्षक बनने से इंकार का विकल्प शेष रहा। अब समझ में आता है कि बाबुओं की फाइलों से जो जानकारी लीक होती है ऊपर वह सब जानकारी होती है। जब और बड़ी व्यवस्था में आए तो बड़े नाम वाले दलाल देखे। जिनपर अंगुली के कट जाने की ज्यादा आशंका होती है। इस बार अध्यापक ही नहीं पत्र का साहित्यकार सभी शामिल होते हैं ऐसा भी देखा जाता है।

घूँघट की बगावत

12 जनवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

राहुल फिर गलत राह पर

देश की राजनीति के मैदान में राहुल गांधी को लगातार गलतियां करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। कई बार तो राहुल गांधी जीता हुआ चुनाव भी हार जाते हैं। आरोप तो यहां तक लगाया जाता है कि राहुल गांधी के इर्द-गिर्द जो नेता रहते हैं, वे चाहते ही नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव जीते। इसलिए कांग्रेस के नेता लगातार राहुल गांधी को अजब-गजब फैसले लेने के लिए उत्साहित और प्रेरित करते रहते हैं।

राहुल गांधी कई बार चुनावी मैदान में सेल्फ गोल करते दिखाई देते हैं तो कई बार गलत ट्रैक पर जाकर रास्ता ही भटक जाते हैं। दिल्ली विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में भी एक बार फिर से राहुल गांधी गलत ट्रैक पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह बात बिल्कुल सौ फीसदी सही है कि कांग्रेस के वोट बैंक को छीनकर ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपराजेय पार्टी के तौर पर स्थापित हुई है लेकिन उतना ही बड़ा सच यह भी है कि कांग्रेस पार्टी अपना वह पुराना वोट बैंक आप से पूरी तरह से छीनने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बेहतर तो यह होता कि कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को पाने के लिए फेज वाइज रणनीति बनाकर, उसे अमल में लाती लेकिन इसकी बजाय कांग्रेस रणनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी गलती करते हुए दिखाई दे रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी खोई जमीन पाने के लिए कांग्रेस एमओएस फॉर्मूला अपनाने जा रही है। यानी कांग्रेस दिल्ली में अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम बहुल सीटों के साथ ही उन विधानसभा सीटों पर फोकस करेगी ,जहां-जहां ओबीसी और दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। हकीकत में कांग्रेस यहीं सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। राहुल गांधी के करीबियों ने उन्हें यह सलाह देकर,एक बार फिर से उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी को गलत ट्रैक पर डाल दिया है। मंडल-कमंडल की राजनीति के दौर के बाद ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग के मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस से विमुख हो चुके हैं और इनकी वापसी की संभावना फिलहाल दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के इस फॉर्मूले का असफल होना तय माना जा रहा है। दरअसल, राहुल गांधी को कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए एमओएस की बजाय बीडीएम के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए जिसके बल

पर जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और मनमोहन सिंह तक देश पर राज कर चुके हैं।

बीडीएम फॉमूर्ले का मतलब है - ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समुदाय। इसी समीकरण के बल पर कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया है। लोक- सभा चुनाव के समय से ही मुस्लिम मतदाताओं के बड़े वर्ग ने कांग्रेस की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भी इस बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का वोट बड़े पैमाने पर कांग्रेस को मिलने की संभावना है और अगर कांग्रेस भाजपा को हराती हुई नजर आई तो पूरा मुस्लिम समाज कांग्रेस उम्मी- दवारों को वोट देते हुए नजर आएगा। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को बीडीएम फॉर्मूले के - ब्राह्मण और दलित को भी अपने साथ जोड़ना होगा। दिल्ली का दलित आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए राहुल गांधी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मान- सम्मान की लड़ाई को और ज्यादा तेज करना पड़ेगा। ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें तो दिल्ली में यह समाज आज की तारीख में भाजपा, आप और कांग्रेस - तीनों ही पार्टियों में बंटा हुआ है। राहुल गांधी अगर थोड़ी सी कोशिश भी करेंगे तो अन्य राजनीतिक दलों के ओबीसी राग से नाराज ब्राह्मण समाज पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में खड़ा नजर आएगा।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 13 जनवरी को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर कर पहली जनसभा कर सकते हैं। राहुल गांधी को जोर-शोर से दिल्ली में चुनावी जनसभाएं, रोड शो और रैलियां करनी ही चाहिए। लेकिन उन्हें कांग्रेस के पूरे चुनाव प्रचार अभियान को इऊ केंद्रित ही बनाना चाहिए और इसे जमीनी धरातल पर उतर कर क्रियान्वित भी करना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण मतदाताओं का बड़े पैमाने पर साथ आना अन्य अगड़ी जातियों को भी कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने के लिए प्रेरित कर सकता है।

कृषि, खनन, निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादन को मिलेगी तेज रफ्तार

जब हम जीडीपी वृद्धि दर में हालिया सुस्ती के कारण पर विचार करें तो पाते हैं कि बीते वर्ष 2024 कई आर्थिक चुनौतियों के कारण जीडीपी में सुस्ती आई है। वैश्विक भू-राजनीतिक कारणों और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों ने विकास दर को प्रभावित किया है। ऊंची ब्याज दर व खपत में कमी का भी प्रभाव पड़ा है। यद्यपि बीते वर्ष 2024 की शुरुआत 8 फीसद विकास दर के साथ हुई थी लेकिन बीते वर्ष की जुलाई से सितम्बर की तिमाही में महज 5.4 फीसद की विकास दर के कारण कई आर्थिक गणित गडबड़ा गए। बीते वर्ष में भारत के आर्थिक परिदृश्य पर प्रमुखतया महंगाई तथा रोजगार चिंताजनक मुद्दे रहे हैं।

महंगाई के मोर्चे पर मुश्किलें लगभग अधिकांश महीनों में बनी रहीं। खासतौर से नवम्बर 2024 के बाद एक बार फिर थोक एवं खुदरा महंगाई बढ़ने लगी और महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित दायरे से बाहर रही। बीते वर्ष में यद्यपि शहरी बेरोजगारी में कमी आई लेकिन असंगठित सेक्टर में रोजगार के मौके घट गए। बीते वर्ष में विदेश व्यापार घाटा भी बढ़ा। बीते हुए वर्ष में रु पया वर्षभर लुढ़कता रहा। वर्षभर डॉलर की तुलना में रु पए की कीमत घटती गई और दिसम्बर 2024 में डॉलर के मुकाबले रोपया लुढ़ककर ८५ से भी नीचे के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2024 में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई । दिसम्बर 2024 में विदेशी मुद्रा कोष घटते हुए करीब 652 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि जीडीपी में बड़ी कमी आई है, लेकिन नये वर्ष 2025 को पिछले बीते वर्ष से आर्थिक विकास के ठोस आधार भी मिले हैं, जिनसे अनुमानित विकास दर बढ़ सकती है। अर्थविशेषज्ञ एक मत से कारोबारी और वित्तीय ऊंचाई को लेकर आशावादी हैं और वे विकास मूलक संकेत देते हुए देश की मजबूत बैलेंस शीट प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कृषि, खनन, निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादन को तेज रफ्तार मिलेगी। नई द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं व नए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) आकार लेते हुए दिखाई देंगे। खासतौर से सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, होटल, ट्रांसपोर्ट, ऑटो मोबाइल, फॉर्मा, केमिकल,फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, टूरिज्म, रिटेल ट्रेड इत्यादि क्षेत्रों में तीव्रता के साथ विकास होगा इससे रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नए वर्ष 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे।

हाल ही में 7 जनवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अग्रिम अनुमान जारी करते हुए कहा कि जीडीपी के इस वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में देखी गई 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि से काफी कम है। ज्ञातव्य है कि पिछले चार वर्षों में और कोविड के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि का यह सबसे निचला स्तर है। यह भी महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास अनुमान को 7.2 प्रतिशत के पहले के अनुमान से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। चूंकि देश में जीडीपी की रफ्तार घटने के बाद अब निकट भविष्य में वैश्विक आर्थिक माहौल अनुकूल होता नहीं दिखता, इसलिए घरेलू नीतियों से वृद्धि को गति देना होगी। नए वर्ष 2025 में जीडीपी की सुस्त रफ्तार को बढ़ाने में स्थानीय और घरेलू बाजार की मजबूती अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगी। पिछले दस वर्षों के दरम्यान देश जिस गति से आत्मनिर्भरता की नीति और वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ा है, उससे नए वर्ष में देश अधिक लाभान्वित होगा।

डेलाइट इंडिया की इंडियाज होम एंड हाउसहोल्ड मार्केट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का घरेलू बाजार दस फीसद से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है।

डेलाइट इंडिया की इंडियाज होम एंड हाउसहोल्ड मार्केट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का घरेलू बाजार दस फीसद से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। निश्चित रूप से नये वर्ष में देश के कोने-कोने में मेक इन इंडिया अभियान की शक्ति बढ़ेगी।

यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस वर्ष बंपर खरीफ और रबी फसल की संभावनाओं के कारण खाद्यान्न की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है। इससे वर्ष 2025 में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

देश में कृषि उन्नयन , खेती में नवाचार को प्रोत्साहन देने, लागत को कम करते हुए उत्पादन के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने का अभूतपूर्व अभियान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकेगा। इसमें कोई दोमत नहीं है कि सरकार को बीते हुए वर्ष से जो बेहतर मानसून विरासत में मिला है, उससे नये वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ेगी, ग्रामीण इलाकों में खपत भी बढ़ेगी। देश में कृषि क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेगा। ज्ञातव्य है कि फसल वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 32.22 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया।

वर्ष 2023-24 में गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन हुआ है। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन 1132.92 लाख टन और चावल का उत्पादन 1378.25 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया। यह अनुमान किया गया है कि सरकार की नई कृषि विकास रणनीति से नए वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। इससे महंगाई पर नियंत्रण होगा और जीडीपी बढ़ेगी।

नए वर्ष में सरकार को बेहतर संभावनाओं को मुट्ठियों में लेना होगा।

भारतीय शेयर बाजार की राह कठिन नहीं होगी, शेयर बाजार को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाने में घरेलू फंड की अहम भूमिका होगी और कार्पोरेट आय को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इसी माह जनवरी 2025 में ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका द्वारा चीन पर भारी व्यापार प्रतिबंधों की संभावना से भारत के नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश बनने की संभावना बढ़ेगी।

कड़कड़ाती सर्दी में राजनीतिक दंगल

दिल्ली में जीत के नये कीर्तिमान गढ़ने वाली नई नवेली आप ने साल 2013 में अपने पहले चुनाव में 70 में से 28 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। उस समय भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन ह्यआपह्ल ने कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई। लेकिन यह सरकार सिर्फ.49 दिनों तक चल पाई। अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2014 में ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि दिल्ली विधानसभा में संख्या बल की कमी की वजह से वो जन लोकपाल बिल पास कराने में नाकाम रहे हैं, इसलिए फिर से चुनाव बाद पूर्ण जनादेश के साथ लौटेंगे। 2015 में जब चुनाव हुआ तो दिल्ली की राजनीति में इतिहास रचते हुए आप ने 70 में से 67 सीटें जीत लीं। वर्ष 2020 में भी आप ने जीत का कीर्तिमान बनाते हुए 62 सीटें जीती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव काफी रोचक होने वाला है लेकिन यह ह्यआपह्य के लिये चुनौतीपूर्ण होने के साथ संकटपूर्ण है। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना आंदोलन के बीच से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, इसी मुद्दे पर भाजपा केजरीवाल को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आप को भाजपा ही नहीं, कांग्रेस से भी बड़ा खतरा है। भाजपा ने अभी अपने पूरे उम्मीदवारों की सूची भी जारी नहीं की है लेकिन चुनाव प्रचार अभियान के लिए पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतार दिया है और उन्होंने अपनी पहली ही चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी पर आक्रामक हमला बोलते हुए उसे दिल्ली के लिये आप-दा यानी बड़ा संकट कह दिया है। आप के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, एलजी ऑफिस के साथ टकराव और कई अन्य फैसले आप की विश्वसनीयता एवं सुदृढ़ता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

आप दिल्ली में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो भाजपा सत्ता विरोधी लहर, शीश महल, भ्रष्टाचार के आरोप को आधार बनाकर उसे रोकना चाहती है। कांग्रेस अपनी खोयी जमीन को पाने की जद्दोजहद में जुटी है। सबसे दिलचस्प एवं रोमांचक इस चुनाव में देखना है दिल्ली की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है?

चुनाव की घोषणा से पहले ही तीनों राजनीतिक दल आम मतदाता को लुभाने के लिये तरह-तरह की घोषणाएं करते हुए जनता से मुखातिब हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। आप तमाम तरह की संकट एवं संघर्षपूर्ण स्थितियों के बावजूद मजबूती बनाये हुए है, क्योंकि आप-सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम, जैसेकि सरकारी स्कूलों का कायाकल्प, मोहल्ला क्लीनिक और मुफ्त बिजली, साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराना उसकी ताकत बनी हुई है। नयी घोषणाओं के साथ वह अपनी इस ताकत को बढ़ाते हुए आप ने महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देने, बुजर्गों को फ्री इलाज, ऑटो चालकों को 10 लाख का बीमा देने, पंडितों एवं ग्रंथियों को 18 हजार प्रतिमाह जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया है, जो पूरे चुनाव का रुख मोड़ सकती हैं। रेवड़ी पर चर्चा जैसी मुहिम से आप हर वोटर के घर तक पहुंच रही है। पब्लिक को बार-बार याद दिला रही है कि उनकी सरकार ने क्या-

क्या काम किए हैं। लेकिन आप के खिलाफ सरकार में 10 साल रहने की वजह से सत्ता विरोधी लहर काफी बढ़ गई है। कई वोटर बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं। दिल्ली का विकास अवरुद्ध है, वायु प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है, यमुना प्रदूषित हो चुकी है, जनता को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, सड़के गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। अरविंद के- जरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। शीश महल विवाद ने अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इससे पार्टी की साफ सुथरी छवि धूमिल हुई है। इसके अलावा मतभेद की वजह से कई नेता छोड़ गए, इससे केजरीवाल की जीत की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। लगता है कि ह्यआपह्ल की उलटी गिनती तो शुरू हो गयी है, देखना है वह कहां जाकर रूकती है।

दिल्ली विधानसभा का चुनाव इसलिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण है कि इसका असर राष्ट्रव्यापी होता है। दिल्ली सरकर की सांविधानिक शक्तियां भले ही सीमित हों, मगर राष्ट्रीय मीडिया के केंद्र में होने के नाते इसके नेताओं को तुरंत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान बन जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि दिल्ली को एक मॉडल स्टेट बनना चाहिए था, मगर न यह विकास का मॉडल बन सका और न ही सुचारू सुशासन प्रणाली का। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था एवं विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर देश की राजधानी की दुर्दशा एवं ठहरा हुआ विकास एक बदनुमा दाग है, विडंबना यह है कि इसके लिए आप सरकार दोषी होते हुए भी क्या आम जनता की अदालत में दोषी साबित होगी? भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों के लिए यह विधानसभा चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला है। पिछले तीन लोकसभा चुनावों से केंद्र में सरकार बनाने वाली और दिल्ली की सभी संसदीय सीटें लगातार जीतने के बावजूद भाजपा पिछले 26 वर्षों से राजधानी की सत्ता से दूर है। यही नहीं, दिल्ली नगर निगम में दशकों से कायम उसकी सत्ता भी छिन चुकी है। ऐसे में इस टीस को वह इस विधानसभा चुनाव में जरूर दूर करना चाहेगी और इसके लिये उसकी तैयारी ही केजरीवाल के लिये संकट का बड़ा कारण है। विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव इसलिए भी रोचक होने जा रहा है क्योंकि इसके नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे और सबसे ज्यादा, आम आदमी पार्टी के भविष्य को तय करेंगे।

दिल्ली की यह चुनावी लड़ाई इस मायने में खास नहीं कही जाएगी कि इस बार भी वही तीनों दल प्रमुखता से मैदान में हैं, जो पिछले चुनावों में थे। आप के अस्तित्व में आने के बाद से यहां त्रिकोणीय मुकाबला ही हो रहा है। यह अलग बात है कि इस अपेक्षाकृत नई पार्टी ने एक बार वर्चस्व स्थापित होने के बाद यहां अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी। पिछले दो चुनावों में उसे दिल्ली की जनता से शानदार बहुमत मिला। नई और दो राज्यों में सत्तारूढ़ होने के बावजूद ह्यआपह्ल ने मुफ्त की संस्कृति एवं आक्रामक शैली की राजनीति से अपनी अलग पहचान बनाई है। इस आक्रामकता एवं मुफ्त की संस्कृति ने जहां ह्यआपह्ल को नई धार दी है, ताकत दी, पहचान दी वहीं अन्य दलों के साथ उसके संबंधों को भी सहज-सामान्य होने से रोका है। धीरे-धीरे उसकी यही ताकत उसकी कमजोरी बनती जा रही है। भाजपा एवं कांग्रेस भी उस पर हमले करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। इसमें खास बात सिर्फ यही है कि छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों ही विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल थे और भाजपा पर संयुक्त हमला कर रहे थे। जाहिर है, इनके बीच की तीखी बयानबाजी इंडिया गठबंधन के अंदर असहजता पैदा कर रही है और शिवसेना (यूबीटी) जैसे दल इनसे संयम बरतने की अपील भी कर चुके हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव-2025 लड़ा जा रहा है, उससे साफ है कि नतीजा चाहे जो भी हो उसके निहितार्थ दूर तक जाएंगे। दिल्ली की सत्ता आप के आंतरिक समीकरण के लिहाज से भी अहम है। ऐसे में वह हर हाल में अपनी कामयाबी दोहराना चाहेगी। लेकिन इस चुनाव में परीक्षा सिर्फ इन राजनीतिक पार्टियों की नहीं, बल्कि दिल्ली के मतदाताओं की भी होगी कि वे अपनी समस्याओं के प्रति कितनी सजगता दिखाते हैं? इस बार दिल्ली की जनता को अपने हित की बजाय दिल्ली के हित में सोचना है। देखना है कि क्या जनता स्वहित के चलते आधे इंजन की सरकार बनायेगी या दिल्ली के समग्र एवं भ्रष्टाचारमुक्त शासन के लिये डबल इंजन की सरकार बनायेगी।

देश का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव-2025 का बिगुल बज चुका है, कड़कड़ाती सर्दी में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के बीच राजनीतिक दंगल के आगाज के साथ राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। उम्मीद की जा रही है कि ठण्ड का पारा गिरने-चढ़ने का रिका- र्ड बनाने वाली दिल्ली इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने के साथ राजनीति उठापटक का भी नया इतिहास बनाएगी। दिल्ली में चुनावों के ऐलान के साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक दूसरे की कलई खोलने की कोशिशें हो रही हैं।

बीबी को खुश करने के चक्कर में देश की जीडीपी डुबोते मजदूर

गत दिनों एल एंड टी कंपनी वाले सुब्रमण्यम ने बेहद ध्यानाकर्षक बात कह दी। बात साधारण सी होकर भी खासी वजनदार महसूस हुई। इतवार की छुट्टी यानी सोमवार, मंगवार, बुधवार, बृहस्पतिवार किसी भी दिन की छुट्टी की मजदूरों-कर्मचारियों को जरूरत ही क्या है? बिल्कुल वक्त की बरबादी। घर पर बैठकर बीबी का चेहरा ताकते रहो, ताकते रहो, ताकते रहो; यह भी कोई करने वाला काम है। इससे अच्छा तो सातों दिन, बारहो महीना कारखाने, दफ्तर में काम करो। पैदावार ज्यादा तो मुनाफा भी ज्यादा और जीडीपी भी ज्यादा और जीडीपी ज्यादा तो सरकार के खजाने में पैसा ज्यादा। यानी मालिक भी खुश और निर्मला ताई भी खुश। सिर्फ बीबी को खुश करने के चक्कर में देश की जीडीपी क्यों डुबो रहे हैं ये मजदूर-वजदूर।

इतनी होशमंदी की बात करने में सुब्रमण्यम अकेले नहीं हैं। उनसे पहले इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति भी यही एडवाइज दे चुके थे। बस वो इतवार वगैरह की छुट्टी के चक्कर में नहीं पड़े थे और सीधे प्वाइंट पर आ गए। दिन में काम के घंटे कम से कम बाहर-चौदह तो होने ही चाहिए और वह देश के प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर रहे थे। जब नारायण मूर्ति की कान में यह बात पड़ी कि मोदी दिन में अठारह-अठारह घंटे काम करते हैं, तो एकदम से उन्हें बोध प्राप्त हो गया। यही तो सारी समस्याओं का समाधान है, सारे रोगों की रामबाण औषधि है। सब ज्यादा घंटे काम करें दो खुद-ब-खुद आगे बढ़ जाएगा। सुब्रमण्यम जी ने गेंद और आगे बढ़ा दी। सवाल उनकी कंपनी में शनिवार की छुट्टी नहीं देने पर पूछा गया था उन्होंने इतवार की छुट्टी को भी नजर लगा दी। सुब्रमण्यम साहब, मूर्ति साहब और मोदी साहब लोगों की बदकिस्मती से इन मजदूरों-वजदूरों के साथ एक बड़ी प्राब्लम है। जब तक काम नहीं मिलता तब तो फिर भी ठीक रहते हैं पर काम मिला नहीं कि ये खुद को इंसान समझने लगते हैं। खुद को तो खुद को अपनी बीबी बच्चों को भी इंसान समझने लगते हैं। उनकी तरफ इंसानों की नजर से देखने लगते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मिडास मंतर से सारे मेहनत करने वालों को मशीन बना दिया जाए? न कोई बीबी को निहारते बैठेगा और न छुट्टी के नाम पर किसी भी दिन की बबार्दी होगी। मजदूरी की झिकझिक भी खत्म।

हर महिला का जीवन व परिस्थिति अलग

देश में शादीशुदा महिलाओं द्वारा पति को बगैर तलाक के छोड़ने और अलग रहने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। यह एक चिंताजनक सामाजिक मुद्दा है। आखिर महिलाएं ऐसे कदम क्यों उठा रही हैं, इसका गहन विश्लेषण संवेदनशील भी है और रोचक भी एक शादीशुदा स्त्री अपने पतिको छोड़नेका निर्णय कई कारणोंसे ले सकती है और यह हर व्यक्तिकी परिस्थितियों, अनुभवों और भावनाओं पर निर्भर करता है। पति-पत्नीका संबंध जटिल होता है और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि स्त्री को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ता है। सबसे पहले, यदि पत्नीको पति की ओरसे भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है तो वह यह कदम उठा सकती है। शारीरिक हिंसा, अपमानजनक व्यवहार, गालियां, मानसिक दबाव या अन्य किसी प्रकार का शोषण व्यक्ति के आत्मसम्मान और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाता है। लंबे समयतक इस तरहके अत्याचारको सहन करना किसीके लिए भी सम्भव नहीं होता और अकसर पनी ऐसी स्थिति से बाहर निकलनेके लिए तलाक या अलगावका कदम उठाती है। यदि पति का विवाहेत्तर संबंध है या उसने धोखा दिया है तो स्त्री के लिए यह बहुत बड़ा आघात हो सकता है। विवाहमें विश्वास और ईमानदारीका बहुत महत्व होता है और जब यह टूटता है तो पत्नीको लगता है कि संबंध को बचाना संभव नहीं है। यदि दोनोंके बीच संचारकी कमी है और वहअपनी भावनाओं, विचारों या समस्याओं को साँझा नहीं कर पाते तो रिश्ते में दरार आ सकती है। लगातार तकरार और अनबन रिश्तेको कमजोर कर देती है। यदि बातचीत से समस्याका समाधान नहीं हो पाता तो महिलां को लगता है कि रिश्ते में कोई भविष्य नहीं है और वह अलग हो जाती है। यदि महिलाको लगता है कि वह अपनी पहचान और करियर में आगे बढ़ सकती है और आर्थिक रूपसे स्वतंत्र हो सकती है तो वह अलगायका कदम उठा सकती है। कभी-कभी पति के साथ लगातार तनाव, संघर्ष और समस्या होनेसे महिलाका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यं प्रभावित हो सकता है। यदि उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता है और वह महसूस करती है कि यह रिश्तेमें बने रहनेसे ठीक नहीं हो रहा है तो वह पतिसे अलग हो सकती है। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की चाहत कभीकभी पत्नीको अलगाव की ओर ले जाती है। कुछ महिलाएं अपने जीवन में व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कारके लिए एक अलग रास्ता अपनाती हैं। यदि वे महसूस करती हैं कि उनके जीवनका उद्देश्य और दिशा 'कुछ और है तो वह अपने पतिसे अलग होनेका निर्णय ले सकती हैं। यह स्थिति तब होती है जब पत्नीको लगता है कि वह अपने जीवनके लक्ष्यों और सपनों को पंतिके साथ मिलकर नहीं पूरा कर सकती। कभीकभी पारिवारिक दबाव, समाज की अपेक्षाएं और संस्कार भी किसी महिला को अपने पति से अलग होनेके लिए प्रेरित करते इस तरहकी स्थितियां विशेषकर तब उत्पन्न होती हैं जब पानीको परिवार या समाज के द्वारा उत्पन्न गलतफहमियों या दबावका सामना करना पड़ता है। यदि पति शराब या किसी अन्य नशेकी लतमें है और इस कारण घरमें शांति नहीं रहती या वह परिवारकी देखभाल नहीं करता तो पत्नीको यह महसूस होता है कि इस रिश्तेका कोई भविष्य नहीं है। इस स्थितिमें वह पति से अलग होनेका निर्णय ले सकती हैं। यदि किसी महिलाको लगता है कि उसका समय व्यर्थ जा रहा है और वह किसी ऐसे व्यक्तिके साथ समय बिता रही है जो उसकी भावनाओं, इच्छाओं या सपनोंको नहीं समझता तो यह उसे इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। घरके वातावरण में शांति और प्यारकी कमी के कारण बच्चोंके मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चोंके लिए बेहतर भविष्य और वातावरण सुनिश्चित करनेके लिए वह अपने पति से अलग होने का निर्णय ले सकती है। हर महिला का जीवन और परिस्थिति अलग होती है और इसलिए यह निर्णय भी व्यक्तिगत और स्थिति विशेष होता है। हालांकि ऐसे निर्णयको लेने से पहले महिलाका अपनी भावनाओं, मानसिक स्थिति और भविष्य बारे पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए।

घटती बेटियां: कोख में ही छीन रहें साँसें, फिर संकट में हरियाणा की 'सुकन्या समृद्धि'

हरियाणा में 2024 में लिंगानुपात आठ साल के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 2024 में गिरकर 910 हो गया है, जो 2016 के बाद सबसे कम है, जब यह अनुपात 900 था। राज्य ने कभी भी डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित आदर्श लिंगानुपात 950 को हासिल नहीं किया है। लड़कों की पसंद के कारण राज्य में लड़कियों की चाहत कम हो गई है क्योंकि उनके परिवारों को डर है कि वे भागकर शादी करने के कारण भविष्य में बदनामी का कारण बन सकती हैं। उनके अनुसार, लड़कियाँ पैसा और संपत्ति कमाकर अपने परिवार की मदद नहीं कर सकती हैं। इसके विपरीत, परिवारों को उनकी शादी में दहेज देना होगा। ऐसी सोच के कारण हरियाणा में लड़कों को शादी के लिए लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। हरियाणा के अधिकांश गांवों में आमतौर पर ऐसी समस्या है।जब तक हरियाणा में लड़के की पसंद में बदलाव नहीं आता, तब तक लिंगानुपात की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम हरियाणा का लिंगानुपात (एसआरबी यानी जन्म के समय लिंगानुपात) राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आठ साल के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। 2024 के पहले 10 महीनों यानी अक्टूबर तक लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया। यह पिछले साल से 11 अंक कम है। वर्ष 2016 में इससे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था। वर्ष 2019 में 923 के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के बाद वर्ष 2024 में हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात घटकर 910 रह गया, जो आठ वर्षों में सबसे कम है। इन आंकड़ों ने हरियाणा के कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों को चिंतित कर दिया है, हालांकि अधिकारियों ने नवीनतम आंकड़ों को रुमामूली उतार-चढ़ावश्र करार दिया है। वर्ष 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के अनुसार भारत में जन्म के समय कुल लिंगानुपात 929 था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित आदर्श लिंगानुपात 950 से हरियाणा बहुत दूर है। राज्य आज तक इस आंकड़े को हासिल नहीं कर पाया है। लिंगानुपात में गिरावट का मतलब है कि राज्य में लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। आर्थिक प्रगति के बावजूद हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग अभी भी बेटों को प्राथमिकता देते हैं। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, लिंगानुपात को लेकर स्थिति में सुधार नहीं होगा। राज्य के लोगों में लड़कों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में अल्ट्रासाउंड संचालकों और गर्भपात केंद्रों का धंधा खूब फल-फूल रहा है। इन राज्यों में ज्यादा सख्ती नहीं है। हरियाणा से लोग दलालों के जरिए यहाँ पहुँचते हैं और जांच व गर्भपात करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड संचालक पैसे के लिए गर्भ में पल रहे भ्रूण की गलत जानकारी भी देते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब लड़कों को लड़की बताकर गर्भपात करवा दिया गया।

अल्ट्रासाउंड करने वाले और गर्भपात करने वाले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले एक दशक में इस पैमाने पर उल्लेखनीय सुधार करने वाले राज्य के लिए यह एक झटका है। 2014 में हरियाणा में लिंगानुपात सिर्फ.871 था। इस पर देशभर में भारी आक्रोश फैल गया और नागरिक समाज संगठनों, राज्य सरकार और केंद्र ने स्थिति को सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए। हरियाणा में गिरते लिंगानुपात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। अभियान के बाद राज्य का लिंगानुपात सुधर कर 2019 में 923 पर पहुँच गया। लेकिन 2020 में इसमें फिर से गिरावट शुरू हो गई, जो अब तक जारी है। हालांकि, तब से लिंगानुपात में एक बार फिर से गिरावट देखी गई है, यह झटका ऐसे समय में आया है जब राज्य की महिलाएँ अंतरराष्ट्रीय मंचों सहित खेलों में और साथ ही शिक्षाविदों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।

2014 और 2019 के बीच हुई बढ़त प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, 1994 (पीएनडीटी एक्ट) के सख्त प्रवर्तन के साथ-साथ गहन जागरूकता अभियान के कारण हुई। इसका उद्देश्य हरियाणा में बड़े पैमाने पर जन्मपूर्व लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना था, साथ ही साथ सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना था, जिसमें परिवार लड़कों को पसंद करते थे और लड़की को बोझ के रूप में देखते थे। हरियाणा में बच्ची के जन्म पर 21, 000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान करने और सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से लड़कियों के लिए बैंक खाते खोलने के बावजूद, बालिकाओं को बोझ के रूप में क्यों देखा जाता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नजरिया बदलने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है और हाल के वर्षों में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन ढीला पड़ गया है।

लड़कों की पसंद के कारण राज्य में लड़कियों की चाहत कम हो गई है क्योंकि उनके परिवारों को डर है कि वे भागकर शादी करने के कारण भविष्य में बदनामी का कारण बन सकती हैं। उनके अनुसार, लड़कियाँ पैसा और संपत्ति कमाकर अपने परिवार की मदद नहीं कर सकती हैं। इसके विपरीत, परिवारों को उनकी शादी में दहेज देना होगा। ऐसी सोच के कारण हरियाणा में लड़कों को शादी के लिए लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। हरियाणा के अधिकांश गांवों में आमतौर पर ऐसी समस्या है। कई परिवारों में अगर लड़कियों का पालन-पोषण ठीक से नहीं किया जाता है तो वे कुपोषण का शिकार हो जाती हैं और कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो जाती है। हरियाणा की आर्थिक तरक्की के बावजूद यहां की बड़ी आबादी की मानसिकता अब भी नहीं बदली है। जब तक लड़कों और लड़कियों में भेदभाव की यह मानसिकता नहीं बदलेगी, हालात बेहतर नहीं होंगे।

-प्रियंका सौरभ

आत्महत्याओं को रोकने की सार्थक पहल का अभाव

भारत में आत्महत्या एक प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 171,000 आत्महत्याएं की गईं थी जो 2021 की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक थी। प्रति एक लाख की जनसंख्या पर आत्महत्या की दर 2022 में बढ़कर 12.4 हो गई जो आंकड़ो के हिसाब से सर्वोच्च थी। 2022 के दौरान आत्महत्याओं में 2018 की तुलना में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और भारत में दुनिया में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुईं। वैश्विक आत्महत्या मौतों में भारत के आंकड़े 1990 में 25.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में महिलाओं में 36.6 प्रतिशत और पुरुषों में 18.7 प्रतिशत से बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गये। 2016 में 15-29 वर्ष और 15-39 वर्ष के आयु समूहों में आत्महत्या मृत्यु का सबसे आम कारण था। दैनिक वेतन भोगी लोग आत्महत्या पीड़ितों का 26 प्रतिशत हिस्सा थे। जो आत्महत्या के आंकड़ों में सबसे बड़ा समूह था। भारत में आए दिन आत्महत्या की घटनाएं घटित होती रहती है। यहां हर चार मिनट में एक आत्महत्या की जाती है। यहां शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब किसी न किसी इलाके से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, कर्ज जैसी तमाम आर्थिक तथा अन्य सामाजिक दुश्वारियों से परेशान लोगों के आत्महत्या करने की खबरें न आती हों। आत्महत्या करना सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक के समान है। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं को दंडित करते हुए अपनी जान दे देता है। ऐसा घिनोना कार्य कोई व्यक्ति तभी करता है जब वह चारों तरफ से निराश हो जाता है। आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक पक्ष को माना जाता है। उसके बाद मानसिक, पारिवारिक व अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर व्यक्ति स्वयं को गिरा हुआ महसूस करता है और अंत में वह आत्महत्या करने जैसा घिनौना कदम उठा लेता है। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि बहुत से परिवारों ने आर्थिक कर्म से सामूहिक आत्महत्या कर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। बहुत से किसान अपना खेती का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण भी बड़ी संख्या में आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कानून तो बना दिया मगर उसका प्रभाव समाज पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेम में असफल होने पर भी बड़ी संख्या में नवयुवक युवतियां आत्महत्या कर अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में राज्यों में सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र (22,746) में हुईं। इसके बाद तमिलनाडु में 19,834 और मध्य प्रदेश में 15,386 आत्महत्याएं हुईं। चार राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल को मिलाकर देश में हुयी कुल आत्महत्याओं में से लगभग आधी उक्त प्रदेशों में हुयी थी। नागालैंड में केवल 41 आत्महत्याएं हुईं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 2017 से 2019 के दौरान भारत में लगभग आधी आत्महत्याएं हुयी हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुईं, उसके बाद पुडुचेरी का स्थान रहा। बिहार और पंजाब में 2018 की तुलना में 2019 में आत्महत्याओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुयी थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच सालों में आत्महत्या की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखता है। 2017 में देश में 1,29,887 आत्महत्याओं की मामले रिकॉर्ड किए गए थे। तब आत्महत्या दर 9.9 प्रतिशत थी। आत्महत्या दर प्रति लाख आबादी पर होने वाली आत्महत्या की घटनाओं को दशार्ता है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति लाख 9.9 आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गईं थी। 2018 में आत्महत्या दर में इजाफा हुआ और ये बढ़ कर 10.2 पर पहुंच गयी थ। तब देश में 1,34,516 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए थे। 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने तो 2020 में ये संख्या बढ़कर 1,53,052 हो गई थी। 2021 में आत्महत्या के 1,64,033 मामले हुये थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि भारत में आत्महत्या की दर विश्व आत्महत्या दर के मुकाबले बढ़ी है। भारत में पिछले दो दशकों की आत्महत्या दर में एक लाख लोगों पर 2.5 फीसद की वृद्धि हुई है। आज भारत में 37.8 फीसद आत्महत्या करने वाले लोग 30 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। दूसरी ओर 44 वर्ष तक के लोगों में आत्महत्या की दर 71 फीसद तक बढ़ी है। 2018 में पारित हुए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत भारत में आत्महत्या के अपराधीकरण का कानून खत्म करते हुए मानसिक बीमरियों से जूझ रहे लोगों को मुफ्त मदद का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून के तहत आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को मदद पहुंचाना, इलाज करवाना और पुनर्वास देना सरकार की जिम्मेदारी होगी।

भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ से जूझ रहे लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोई ठोस बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन विश्व के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग आठ लाख लोग आत्महत्या करते हैं। जिनमें से 21 फीसदी आत्महत्याएं भारत में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में सरकारों को सलाह दी गई है कि आत्महत्या का मीडिया ट्रायल नहीं हो। देश में अल्कोहल को लेकर ठोस नीति बनाई जाए। आत्महत्या के संसाधनों पर रोक लगाते हुए आत्महत्या के प्रयास करने वालों की उचित देखभाल की जाए। आत्महत्या जैसे मामलों को रोकने के लिए समाज के हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को सामने आने की जरूरत है। जिससे ज्यादा-से-ज्यादा लोग इस बात से जागरूक हो सकें और आत्महत्या जैसे मामलों में कमी लाई जा सके। सभी को इस बात को समझने की जरूरत है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिन्दगी में तनाव की स्थिति कभी कम तो कभी ज्यादा बनी रहती है। परंतु इसका समाधान अपनी जिन्दगी को समाप्त कर लेना नहीं हैं। जानबूझकर खुद को मारना आत्महत्या या ह्लफेलो डे सेह्व के रूप में जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 309 आत्महत्या से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी आत्महत्या का प्रयास करेगा और इस तरह के अपराध को अंजाम देगा उसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, जुमार्ना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या के मामलों के अध्ययन के बाद सरकार और गैर-सामाजिक संगठनों को मिल कर एक ठोस पहल करनी होगी। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाना होगा। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की ठोस रणनीति के बिना देश में बढ़ती आत्महत्यों पर रोक लगाना मुश्किल होगा। सरकार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आर्थिक-सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की गहराई से पड़ताल करनी चाहिये। साथ ही ऐसे उपाय करे कि लोग अपनी जीवनलीला समाप्त करने का विचार ही दिमाग में न लाए। आंकड़ों की दृष्टि से भारत आत्महत्याओं के मामले में दुनिया में सिरमौर बनता जा रहा है। आत्महत्या रोकने की दिशा में अब तक सरकारी स्तर पर जितने भी प्रयास हुए हैं वह सब नाकाम साबित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों में जितनी आत्महत्या की संख्या दशार्यी जाती है उससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या कर अपनी जान गंवा रहे हैं। मगर आत्महत्या की घटनाओं को रोकने की कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है। खेती के लिए लिया गया कर्ज.नहीं चुका पाने के कारण भी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मगर सरकारी बैंकों, साहूकारों के कर्ज से परेशान किसान आज भी आत्महत्या कर रहें हैं। उन्हें रोकने की दिशा में भी सरकार ने कोई विशेष पहल नहीं की है। बैंक आज भी किसानों से जबरदस्ती कर्ज वसूली के लिए उनकी जमीने नीलाम कर रहे हैं। इसी के चलते किसान मजबूर होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं।

महाकुम्भ में साधु संतो से हिंदुत्व पर चर्चा, वक्फ पर कसेगा शिकंजा

तर्क की कसौटी पर कसिये, यूपी में एक योगी मुख्यमंत्री है और यूपी में ही इस बार महाकुम्भ है और हिंदू राष्ट्र और वक्फ जैसे मुद्दे भी चरम पर है तो बात हास्यास्पद ही लगेगी की योगी संत शिविर में जाए और बिना इन मुद्दों पर विचार विमर्श किए लौट आए। महाकुम्भ में पहुँच व्यक्ति जीवन की सारी ऊंच-नीच, लाभ-हानि, मिलना-बिछुड़ना देख चुका व्यक्ति अंततः तर्कों से मुक्त हो जाता है। समय के सामने हर 'तर्क' को पराजित होते देखने के बाद व्यक्ति की झोली में केवल श्रद्धा बचती है, और वह श्रद्धा आपसे कम से कम इतना समय अवश्य मांगती है की आप विशेष आयोजनों में संतो का सानिध्य प्राप्त करें। इस बात को समझ लें कि यूपी में वक्फ बोर्ड के दिन अब ज्यादा दिन लम्बे नहीं हैं। हर जमीन पर अपना झंडा गाड़ने वाले वक्फ बोर्ड को 1989 में कांग्रेस के एनडी तिवारी सरकार ने प्रदेश की तमाम बंजर जमीन वोट बैंक बनाए रखने के लिए सौंप दी थी। योगी सरकार ने उन कानूनों के चलते बहुत कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिन पर वक्फ बोर्ड में कोहराम मचा है। सम्भल में मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी बन रही है। वक्फ बोर्ड ने इस पर भी अपना दावा ठोक दिया है। तो जाहिर है कि अब यह लड़ाई प्रशासन बनाम वक्फ हो जाएगी। कोहराम और तेजी से मचेगा और बात बहुत आगे तक जाएगी। देखते जाइए, मामला काफी गंभीर है। वैसे समय आ गया है कि वक्फ बोर्ड को देश भर में भंग कर दिया जाए। पीवी नरसिंहराव और मनमोहन सिंह सरकार ने वही सब देश में कर डाला जो तिवारी सरकार ने यूपी में किया था अर्थात ऐसे बवालों पर चुप्पी मार गए। मोदी सरकार वक्फ कानूनों में संशोधन करने के लिए बिल लाएगी। यह बिल अभी जेपीसी में है और पास होने में संशय है। लेकिन यूपी में योगी राज है, योगी ने संभल के रास्ते जो मुहिम शुरू की है, उसका असर पूरे देश में जाने वाला है। सवाल उठता है कि वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं कि कुम्भ की जमीन पर, कॉलेज की जमीन पर, संसद की जमीन पर भी वह अपना दावा ठोक दे और सुप्रीमकोर्ट की जमीन पर भी ? सिर्फ वोट बैंक बनाए रखने के लिए या फिर गरीब मुसलमानों तक की जमीन भी कब्जाने के लिए ? एक जमाने में अखिलेश के दाहिने हाथ आजम खान ने वक्फ की आड में जितनी जमीन रामपुर में कब्जाई थी उसकी 80% गरीब मुसलमानों की थी। निश्चित रूप से यूपी में योगी सरकार न आई होती तो आजम खान जेल न जाते और 89 गरीब मुसलमानों को उनकी जमीनें वापस न मिलती। अब देखिए न संभल घटनाक्रम, मस्जिद के कानूनी सर्वे, अनेक मंदिर एवं कुएं निकलने, एएसआई सर्वे और पुलिस चौकी बनने से अखिलेश आगबबूला हैं ? जनता की नब्ज को पढ़े बिना विपक्षी दलों की यह हठधर्मिता उन्हें पहले ले डूबी थी, आगे भी डुबो दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।उधर महाकुम्भ में पहुँच, एक आयु के बाद व्यक्ति ईश्वर से भौतिक सुख मांगना भी छोड़ देता है। क्या करेंगे गाड़ी घोड़ा, क्या करेंगे सोना चांदी अब उसे हिंदू राष्ट्र चाहिए ! अब तो चला चली की बेला है तों अपने पीढ़ी के लिए स्वर्ग मांग ले इस लोक में। उसे जो भोगना था भोग लिए, अब बस वह लोक सुधर जाय। इसी के लिए वह हर स्थान पर शीश नवाता है, हर तीरथ नहा लेता है। जाने कौन किस घाट पर गङ्गा मइया जीवन के अपराध क्षमा कर दें। तीरथ तीरथ मुक्ति ढूंढते लोग। वृद्धावस्था की उम्र में श्रद्धा देखने वालों में भी हरि निवास करते है। थके अशक्त शरीर लगभग ढोते हुए, घाट घाट घूम कर देव को ढूंढते लोगों को देख कर सहज हिन्दू मन अनायास ही कह उठता है- इनकी सुन लेना प्रभु! इनकी सुन ली जानी चाहिये। जबतक व्यक्ति के देह में शक्ति है तबतक उसके लिए कुम्भ प्रयाग हरिद्वार में लगता है, जब शक्ति क्षीण हो जाय तब कांवड़ के कुम्भ में ही गङ्गा जमुना सरस्वती उतर आती हैं। इसी सहजता का नाम सनातन है।

पंकज सीबी मिश्रा

चीन में एचएमपीवी का प्रकोप कोरोना के बाद नया खतरा

2020 में चीन से हुई कोरोना की शुरूआत के बाद इसने पूरी दुनिया में जो दहशत मचाई, उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोरोना महामारी के भयावह दौर में दुनियाभर लाखों लोग मारे गए, लाखों परिवार उजड़ गए, अनेक बच्चे अनाथ हो गए। अभी तक कोरोना का खौफ बरकरार है और कोरोना की शुरूआत के करीब 5 साल बाद अब चीन से ही एक और ऐसे ही खतरनाक वायरस की दस्तक की खबरें दुनिया के सामने आ रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुछ बच्चों में नए वायरस के मामले मिल चुके हैं, जिसके बाद भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। कमजोर प्रतिरक्षा वाले रोगियों में यह संक्रमण निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और उनमें मौत का जोखिम बढ़ जाता है। हाल के दिनों में कई रिपोर्टों में बताया जा चुका है कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) नामक इस वायरस ने इन दिनों चीन में दस्तक देकर वहां दहशत फैला रखी है और इस खतरनाक वायरस के कारण वहां के अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है तथा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के कारण बड़ी संख्या में मरीज मर भी रहे हैं लेकिन कोविड की ही भांति चीन द्वारा इसे लेकर भी लीपापोती की जा रही है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

दरअसल विदेशी मीडिया पर लगे प्रतिबंधों के कारण चीन से कोई भी खबर दुनिया तक आसानी से नहीं पहुंच पाती, केवल चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ही खबरों का एकमात्र जरिया है, जो दुनिया को वही खबर बताती है, जो वहां की सरकार चाहती है। बताया जा रहा है कि उत्तर चीन के प्रांतों में 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों में एचएमपीवी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस खतरनाक वायरस के हमले से चीन में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। खचाखच भरे अस्पताल और श्मशान में बढ़ती बेतहाशा भीड़ इस संकट के कोरोना जैसा या उससे भी बदतर होने की पुष्टि कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ह्यसार्स-सीओवी-2 (कोविड-19)ह्व नामक एक एक्स हैंडल द्वारा पोस्ट में लिखा गया है कि चीन इस समय एचएमपीवी, इन्फ्लूएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरस के मामलों में उछाल का सामना कर रहा है और वहां के अस्पताल विशेष रूप से निमोनिया और ह्यव्हाइट लंगह्व के मामलों से परेशान हैं।

पूरी दुनिया के लिए महासंहारक साबित हुए कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति को लेकर भले ही चीन आरोपों को खारिज करता रहा लेकिन बार-बार यह पुष्टि होती रही कि वह वायरस चीन के वुहान शहर से ही दुनिया में फैला था लेकिन वुहान में यह कैसे फैला था, उस रहस्य से पर्दा अब तक नहीं उठ सका है और अब एचएमपीवी वायरस का प्रकोप भी सबसे पहले चीन में ही शुरू हुआ है। दरअसल बर्ड फ्लू से लेकर सार्स और कोविड तक सभी प्राणाघातक और महासंहारक वायरल रोगों की उत्पत्ति चीन से ही होती रही है लेकिन इसका रहस्य दुनिया आज तक पता नहीं लगा पाई है। चूंकि सभी वायरस चीन में ही पैदा हो रहे हैं, इसलिए ऐसे वायरस हमलों को लेकर पूरी दुनिया में चीन को लेकर संदेह का माहौल बना हुआ है कि कहीं कोविड-19 के बाद खतरनाक होता एचएमपीवी भी चीन की जैविक प्रयोगशालाओं में रची जा रही साजिश तो नहीं है। कोविड संकट के दौरान विश्व के तमाम देशों की औद्योगिक गतिविधियों सहित जनजीवन भी पूरी तरह ठप्प हो गया था। उस दौरान चीन को छोड़कर तमाम देशों की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म होने के कगार पर आ गई थी। कई देश तो इसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं।

एचएमपीवी वायरस के संक्रमण की तेज गति को देखते हुए इसके अन्य देशों में फैलने के खतरों से इन्कार नहीं किया जा सकता। हालांकि डच शोधकताओं ने 2001 में सबसे पहले श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित बच्चों में इस वायरस की खोज की थी और हर साल कई देशों में इसके कुछ मामले सामने आते रहे हैं लेकिन इन दिनों चीन में जिस तरह इस वायरस ने आतंक मचाया हुआ है, ऐसे में चीन में इसके बेतहाशा बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है तथा लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मौसमी इन्फ्लुएंजा और सांस संबंधी संक्रमणों की निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डा. अतुल गोयल का कहना है कि खबरों में कहा जा रहा है कि चीन में मेटान्यूमोवायरस वायरस का एक आउटब्रेक है, जो गंभीर है। हालांकि उनका कहना है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि भारत में किसी गंभीर स्थिति की संभावना है। वहीं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन और बाल रोग विशेषज्ञ डा. अरूण गुप्ता का कहना है कि भारत में इस वायरस के कारण बीमारी बढ़ने की अभी संभावना नजर नहीं आ रही है।

अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार, एचएमपीवी सभी उम्र के लोगों में अपर और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण बन सकता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से निकलने वाले स्राव या नजदीकी संपर्क जैसे हाथ मिलाने से भी फैलता है। एचएमपीवी वायरस न्यूमोवायराइड और मेटान्यूमोवायरस जीनस का हिस्सा है, जो एक सिंगल-स्ट्रैंडेड नेगेटिव-सेंस आरएनए वायरस है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, इस वायरस का संक्रमण काल तीन से पांच दिन होता है। इस वायरस के संक्रमण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे यह बार-बार संक्रमण का कारण बन सकता है। एचएमपीवी भी कोरोना की ही भांति श्वसन पथ को संक्रमित करता है, हालांकि कोरोना के मुकाबले इस वायरस के कारण ऊपरी और निचले दोनों श्वसन पथ में संक्रमण का खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह एक कम पहचाना गया वायरस है लेकिन यह दुनियाभर में मौसमी श्वसन बीमारियों में योगदान कर रहा है। एचएमपीवी में कोरोना ही भांति फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। इससे जुड़े सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि शिशुओं और बुजुर्गों, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उनमें मेटान्यूमोवायरस के कारण गंभीर बीमारी होने का खतरा अधिक होता है। इससे बचाव के उपायों में हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोना, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक ढंकना, संक्रमितों लोगों से दूरी बनाना, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद लेना, फ्लू के टीके लगवाना इत्यादि शामिल हैं।

2024 विज्ञान समीक्षा: वैज्ञानिक प्रगति, जिसमें नई एचआईवी रोकथाम दवा की खोज, क्वांटम कंप्यूटिंग, प्रगति, माइक्रोप्लास्टिक्स ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं...

दुनिया की वेधशालाओं, क्षेत्रीय अध्ययनों और प्रयोगशालाओं में की गई कुछ खोजें। उनमें से कुछ निष्कर्ष हमें स्वस्थ बना सकते हैं, जबकि अन्य ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान की बाहरी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। एक दवा जो एचआईवी को रोकती है एचआईवी/एड्स के खिलाफ टीका विकसित करने के लगभग 40 वर्षों के असफल प्रयासों के बाद, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा ढूंढ ली है जो वर्ष में केवल दो बार इंजेक्शन लगाने पर संक्रमण को रोकती है। दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में 2024 में समाप्त हुए एक नैदानिक परीक्षण में 2,134 महिलाओं और लड़कियों के बीच 100% प्रभावकारिता दिखाई गई। नियंत्रण समूह में, लड़कियों और युवा महिलाओं को मौजूदा रोकथाम दवाएं दी गईं, जिन्हें पीआरईपी भी कहा जाता है, जिन्हें दैनिक गोली के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। जबकि पीआरईपी ने सैन फ्रांसिस्को में एचआईवी के नए मामलों को लगभग समाप्त कर दिया है, अफ्रीका में कलंक महिलाओं के लिए नियमित रूप से दवा लेना कठिन बना देता है। विज्ञान ने साल में दो बार मिलने वाली नई दवा, लेनकापाविर को 2024 ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर नाम दिया है। गिलियड द्वारा बनाई गई नई दवा, वैक्सीन की तरह काम नहीं करती है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसे टीके को नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी लागत कम होने की संभावना है और जो लोगों को स्थायी रूप से सुरक्षित कर सके। गिलियड दवा को 2025 के मध्य में मंजूरी मिलने की संभावना है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह उन लोगों के लिए सस्ती और सुलभ होगी या नहीं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। एआई मानव मानस में गहराई से उतरता है एआई विज्ञान के हर क्षेत्र को हिला रहा है, लेकिन सामाजिक वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग विशेष रूप से विशिष्ट नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया है। वे मनुष्यों के सोचने के तरीके का अध्ययन करने के लिए बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करते हैं और उन तरीकों का पता लगाते हैं जिनसे हम बेहतर सोच सकते हैं। सितंबर में प्रकाशित एक अध्ययन में, मनोवैज्ञानिकों ने खुद को आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने साजिश सिद्धांतकारों को यह मानने के लिए एआई चैटबॉट को प्रशिक्षित किया कि वे गलत हो सकते हैं। इसने काम किया। लोगों ने विदेशी लैंडिंग को छुपाने या जैविक हथियारों के साथ जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए नापाक साजिशों में अपना विश्वास छोड़ दिया। षडयंत्र सिद्धांतकार अक्सर अपने विश्वासों का समर्थन करने के लिए संदिग्ध सबूतों के ढेर इकट्ठा करते हैं, जिससे उन इंसानों को थका दिया जाता है जिनके पास बनाए रखने के लिए समय या ऊर्जा नहीं होती है। सबूतों की मात्रा के मामले में चैटबॉट उनका मिलान कर सकते हैं। इस वर्ष प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि एआई द्वारा सही उत्तर सुझाए जाने के बाद भी डॉक्टर अक्सर गलत निदान करते हैं। चैटजीपीटी-4 के खिलाफ निदान प्रतियोगिता में भाग लिया गया, तो ऐआई ने केस रिपोर्ट से ली गई 90% स्थितियों का सही निदान किया, जबकि डॉक्टरों ने 74% सही पाया। जब डॉक्टरों को एआई से परामर्श करने की अनुमति दी गई, तो वे केवल 76% मामलों में ही सटीक थे। वे अपने पहले अंतर्ज्ञान के बारे में बहुत आश्वस्त थे। एआई से पूरी तरह से लाभ उठाने में डॉक्टरों की विफलता से पता चलता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है कि उन्हें इस–ाका उपयोग करने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाता है और एआई को उनकी मदद के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार, एआई लोगों को समाचारों की तथ्य-जांच में मदद करने में बहुत अच्छा नहीं था। चैटजीपीटी-4 ने कभी-कभी लोगों के अनिश्चित होने पर नकली सुर्खियों में विश्वास बढ़ा दिया और जब कोई त्रुटि हुई तो उन्हें वास्तविक सुर्खियों पर अविश्वास करने पर मजबूर कर दिया।

एआई तब सबसे अच्छा काम करता प्रतीत होता है जब यह हमें अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करता है, न कि तब जब हम अपने बारे में सोचने के लिए इस पर भरोसा करते हैं। जहाज सुदूर समुद्री दुनिया के लिए रवाना हुआ 14 अक्टूबर को, 5 बिलियन डॉलर का अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर बजट कटर की पहुंच से काफी ऊपर चला गया और हमारे सौर मंडल में अलौकिक जीवन के सबसे आशाजनक निवास की यात्रा पर निकल पड़ा। यूरोपा, बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा, सतह पर एक अच्छी जगह की तरह नहीं दिखता है, जहां बर्फ की मोटी परत है और तापमान कभी भी इससे ऊपर नहीं जाता है।-120सी. लेकिन पिछले फ्लाईबाई मिशनों में सतह के नीचे एक विशाल महासागर के खिसकने और कभी-कभी फटने के संकेत मिले थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यूरोपा में पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में लगभग दोगुना पानी है, जो बृहस्पति के राक्ष–ासी ज्वारीय बल द्वारा उत्पन्न घर्षण से गर्म होता है। खगोलविज्ञानी तरल पानी को जीवन के लिए प्रमुख घटक मानते हैं - कम से कम उस तरह के जीवन को पृथ्वीवासी पहचान सकते हैं। जब यह 2030 में आएगा, तो यान सतह पर दर्जनों उड़ान भरेगा, अपने उपकरणों का उपयोग करके अणुओं को सूँघेगा जो पोषक तत्वों के रूप में काम कर सकते हैं और नीचे बर्फ और महासागर का नक्शा तैयार कर सकते हैं। यदि परिणाम आशाजनक रहे, तो एक लैंडर पीछा कर सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप सार्वभौमिक विस्तार की पुनर्गणना करता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे जेडब्लूऐसटी के नाम से भी जाना जाता है, की बदौलत इस वर्ष हमारे सुदूर ब्रह्मांड के नए पहलू सामने आए। शिकागो विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री वेंडी फ्रीडमैन ने कहा, दूर की आकाशगंगाओं पर प्रशिक्षित, इसने सितारों को ₹बाहर निकलते₹ दिखाया, जहां हबल ने हल्के धब्बे दिखाए। इससे उसे उस दर की पुनर्गणना करने की अनुमति मिली जिस पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यह सब इस बात का पता लगाने की एक बड़ी खोज का हिस्सा है कि ब्रह्मांड का विस्तार क्यों हो रहा है और हम सब कहाँ जा रहे हैं - एक नाटकीय पतन या विस्मृति की ओर। वैज्ञानिक उस अवधि को भी देख रहे हैं जिसे ₹कॉस्मिक डॉन₹ के रूप में जाना जाता है, जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु का 1% था और उनके भीतर की सभी आकाशगंगाओं और सितारों ने सबसे पहले प्राइमर्डियल गैसों से आकार लिया था। इसलिए जब उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अब तक देखी गई सबसे दूर की आकाशगंगा पर कब्जा कर लिया है - यह समय की सबसे गहरी भी थी, जो 13 अरब साल से भी अधिक पहले की प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों का उपयोग करके 2001 में विस्तार दर को पकड़ लिया था। हालाँकि, यह बिग बैंग के बचे हुए विकिरण, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है, का उपयोग करके किए गए माप से मेल नहीं खाता। फ्रीडमैन का कहना है कि उनके समूह ने इस विकिरण के व्यवहार के साथ जेडब्लूऐसटी वर्ग के साथ नए माप किए। इस कार्य के लिए उन्हें प्रकृति के वर्ष के शीर्ष 10 वैज्ञानिकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई।

अन्य, जेडब्ल्यूएसटी का उपयोग करते हुए, तेजी से विस्तार को मापते हैं और तर्क देते हैं कि अन्य मापों के साथ असंगति ब्रह्मांड हमें यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कुछ नई भौतिक घटनाएं चल रही हैं। जहाँ तक हमारे भाग्य की बात है, हम अभी भी एक संकट में समाप्त हो सकते हैं या हमेशा के लिए विस्तारित हो सकते हैं - यह अभी भी अज्ञात है। 44 और 60 की उम्र में बुढ़ापा तेजी से बढ़ता है उम्र बढ़ने के खतरों से लड़ने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी परियोजना में, आनुवंशिकीविद् माइकल स्नाइडर और उनके सहयोगियों ने 108 स्वयंसेवकों से रक्त और अन्य जैविक नमूने लिए। उन्होंने कुल 135,239 सूक्ष्मजीवों और अणुओं के संयोजन में उम्र से संबंधित अदृश्य परिवर्तनों की निगरानी की। इससे एक आश्चर्यजनक पैटर्न सामने आया - जब लोग 44 वर्ष के हो जाते हैं और फिर 60 वर्ष के हो जाते हैं, तो अचानक आणविक-स्तर में बदलाव होता है। परिवर्तनों ने मांसपेशियों के नुकसान, हृदय के खराब स्वास्थ्य और वसा, शराब और कैफीन को चयापचय करने की क्षमता में कमी का संकेत दिया। 60 के आसपास, अधिक परिवर्तनों ने प्रतिरक्षा प्रणाली के पतन का संकेत दिया।

सबसे पहले, शोधकताओं ने सोचा कि 44 की उम्र में बदलाव महिलाओं में पेरिमेनोपॉज से जुड़ा था। हालाँकि, डेटा से पता चला कि पुरुषों में भी यही हो रहा है, जिसका अर्थ है कि या तो उम्र बढ़ने की यह वृद्धि रजोनिवृत्ति से स्वतंत्र रूप से होती है या पुरुष रजोनिवृत्ति वास्तविक है। स्नाइडर ने कहा कि ये परिवर्तन लोगों को लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हस्तक्षेपों का लक्ष्य हो सकते हैं और अंततः मानव जीवन काल को बढ़ाने के तरीकों को जन्म दे सकते हैं। गहरे समय में जलवायु का पुनर्निर्माण पृथ्वी की जलवायु के एक नए पुनर्निर्माण से पता चलता है कि इसमें युगों के दौरान बेतहाशा उतार-चढ़ाव आया। वैज्ञानिकों ने दुनिया को चौंका दिया1990 के दशक में पिछले हजार वर्षों के ग्राफ के साथ, प्राकृतिक रिकॉर्ड का उपयोग करके 20वीं शताब्दी में बढ़ते तापमान को प्रकट किया गया। यह 485 मिलियन वर्ष पीछे चला जाता है - डायनासोर से पहले, जंगलों से पहले, मछलियों द्वारा खुद को आदिम तटों तक खींचने से पहले। इससे पता चलता है कि पिछले 485 मिलियन वर्षों में, जलवायु में ₹हॉटहाउस₹ अवधियों के बीच उतार-चढ़ाव आया जब वैश्विक तापमान अब की तुलना में 30ऋअधिक गर्म हो सकता है, और अस्थिर ₹आइसहाउस₹ अवधियों के बीच जब तापमान हिमयुग और हाल ही में अधिक समशीतोष्ण चरणों के बीच होता है। इतिहास। कभी-कभी, जीवित चीजें सबसे गर्म मौसम के अनुकूल हो जाती हैं, दरियाई घोड़े और उष्णकटिबंधीय ताड़ के पेड़ धीरे-धीरे आर्कटिक की ओर पलायन करते हैं। जब परिवर्तन अचानक हुआ, तो जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि 80% से 90% प्रजातियाँ विलुप्त हो गईं, हालाँकि जीवन कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कथानक बनाने वाले शोधकताओं का कहना है कि यह हमारे जलवायु मॉडल का एक उपयोगी परीक्षण रहा है - वे समय में वापस आने वाले इन माप-आधारित अनुमानों से मेल खाते हैं। इसलिए और अधिक तीव्र गर्मी आ रही है। अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी संभवतः लाखों वर्षों तक एक जीवित ग्रह बनी रहेगी। वर्ष का स्वास्थ्य संबंधी भयः आपके मस्तिष्क में प्लास्टिक मैंने पहले ही प्लास्टिक को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन नए साल का आगमन मुझे और अधिक प्रेरणा दे सकता है।

मुझे प्लास्टिक पसंद नहीं है, लेकिन मुझे प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन और पेय की सुविधा पसंद है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हममें से अधिकांश लोग पूरी तरह से छोड़ सकते हैं - सामान हर जगह है, नल के पानी, मांस, पोल्ट्री और समुद्री भोजन में रिस रहा है। इस साल, कई चौंकाने वाले अध्ययनों से पता चला है कि प्लास्टिक के कण हमारे अंगों में जमा हो रहे हैं। चूहों में, माइक्रोप्लास्टिक पुरुषों की प्रजनन क्षमता, सीखने और याददाश्त को खराब करता है। हम ठीक से नहीं जानते कि ये कण हममें क्या करते हैं, लेकिन यह अच्छा नहीं हो सकता। एक अध्ययन में पाया गया कि धमनियों में बनने वाली पट्टिका में प्लास्टिक होता है, और अधिक प्लास्टिक स्ट्रोक या दिल के दौरे के उच्च जोखिम से जुड़ा होता है।

एक समीक्षा लेख में प्लास्टिक को ऑक्सीडेटिव तनाव से जोड़ा गया है, जो उम्र बढ़ने से जुड़ा है। लेकिन जिस बात ने वास्तव में मेरे अंदर डर पैदा कर दिया वह पिछली गर्मियों में एक अध्ययन की प्रीप्रिंट जारी की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि माइक्रोप्लास्टिक शायद हमारे दिमाग में जमा हो रहा है। शोधकताओं ने 91 लोगों के शव परीक्षण के दौरान प्लास्टिक की खोज की और पाया कि उनके दिमाग में अन्य अंगों की तुलना में 20 गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक जमा हो गया था। जो लोग अल्जाइमर से मरे थे उनके दिमाग में उन लोगों की तुलना में अधिक प्लास्टिक था जो स्वस्थ थे लेकिन दुर्घटनाओं या हिंसा से मर गए। जनवरी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि पानी की एक सामान्य बोतल में प्लास्टिक के लगभग 240,000 अदृश्य कण होते हैं, इसलिए प्लास्टिक की बोतलों में पेय को कम करना समाधान के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। मृत्यु और मनोभ्रंश से लड़ने के लिए सर्वोत्तम व्यवसाय इस वर्ष जारी किए गए दो अध्ययनों ने इस बारे में कुछ आकर्षक संकेत दिए हैं कि मानसिक गिरावट को टालने और ग्रिम रीपर को रोकने की सबसे अधिक संभावना कौन है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के क्रिसमस अंक में जारी एक में सीडीसी आंकड़ों का उपयोग करके दिखाया गया है कि एम्बुलेंस और टैक्सी चालकों में अल्जाइमर रोग से मरने की संभावना अन्य व्यवसायों के लोगों की तुलना में कम थी। पिछली गर्मियों में जारी एक अन्य अध्ययन में, शोधकताओं ने पुरुष पेशेवर एथलीटों की तुलना की और पाया कि पोल वाल्टर्स और जिमनास्ट सबसे लंबे समय तक जीवित रहे, और वॉलीबॉल खिलाड़ी आश्चर्यजनक रूप से अल्पकालिक थे। खेल अध्ययन के मुख्य लेखक ने मुझे बताया कि पोल वॉल्टर्स और जिमनास्ट के प्रशिक्षण नियमों में कुछ फायदेमंद हो सकता है और कम जीवन प्रत्याशा वाले कई एथलीटों ने ऐसे खेल खेले जिससे उन्हें चोटों का खतरा था, खासकर सिर पर चोट लगने का। टैक्सी अध्ययन उत्साहितवैज्ञानिकों को, क्योंकि इसने 2000 की एक दिलचस्प खोज को ध्यान में रखा। आम जनता की तुलना में, लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के पास अधिक विकसित हिप्पोकैम्पस था - मस्तिष्क का वह हिस्सा जो स्मृति और नेविगेशन कौशल से जुड़ा होता है। निःसंदेह, यह तब की बात है जब वे जीपीएस का उपयोग नहीं करते थे। नए साल के संकल्प के हिस्से के रूप में टैक्सी ड्राइविंग या पोल वॉल्टिंग पर विचार करने से पहले, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दोनों अध्ययन प्रारंभिक हैं। लेकिन इस तरह के अध्ययन वैज्ञानिकों को नई दिशाएं स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर एक बड़ा कदम इस वर्ष तक, क्वांटम कंप्यूटिंग उन स्वप्न प्रौद्योगिकियों में से एक थी जो कुछ भी उपयोगी करने से हमेशा के लिए एक दशक दूर रही। अब, चीजें उम्मीद से ज्यादा तेजी से हो रही हैं। कई समूहों ने एक बड़ी बाधा - एक त्रुटि समस्या - को हल कर लिया है। सूचना भंडारण की इकाइयाँ - जिन्हें क्वबिट कहा जाता है - इस तरह से त्रुटि-प्रवण थीं कि उन्हें एक साथ जोड़ने से त्रुटि दर कई गुना बढ़ गई। यदि आशावादी भविष्यवाणियों का नवीनतम दौर सफल होता है, तो क्वांटम कंप्यूटर वास्तविक दुनिया की जटिलता को पचाकर अन्यथा असंभव भविष्यवाणियां कर सकते हैं - उदाहरण के लिए, प्रायोगिक दवाएं मानव शरीर में कैसे काम करेंगी, या कुछ नई प्रकार की सामग्री तनाव को कैसे संभालेंगी। जबकि सामान्य कंप्यूटर बिट्स में जानकारी संग्रहीत करते हैं, जो 0 या 1 मान ले सकते हैं, एक क्यूबिट बीच में कोई भी मान ले सकता है। क्यूबिट में सुपरकूल पदार्थ या परमाणु शामिल हो सकते हैं जो लेजरों से सीमित होते हैं। पिछली गर्मियों में, माइक्रोसॉफ्ट और स्टार्टअप क्वांटम और गूगल ने घोषणा की कि वे प्रगति कर रहे हैं।

वे क्वैबिट को एक साथ जोड़ने में सक्षम थे जिससे त्रुटि दर बढ़ने के बजाय कम हो गई। गूगल ने त्रुटि सुधार को और भी आगे बढ़ाते हुए विलो नामक चिप में 105 क्यूबिट को जोड़ा, जिसकी घोषणा इस महीने नेचर जर्नल में की गई थी। बड़ी बिक्री लाइन यह थी कि विलो को एक परीक्षण समस्या को हल करने में पांच मिनट लग सकते थे जो सुपर कंप्यूटर 10 सेप्टिलियन वर्षों या ब्रह्मांड की आयु वर्ग में नहीं कर सकते थे। परीक्षण समस्या कुछ भी उपयोगी नहीं थी, और विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक दुनिया की समस्याएं अधिक जटिल हैं। लेकिन यह एक सत्तर साल से भी कम समय में, शायद 2030 तक, शुरू हो जाना चाहिए, अगर कोई नया मुद्दा इसे लगातार पाँच साल दूर न रखे।

विजय गर्ग
मलोट पंजाब

युवा शक्ति की प्रेरणा

विश्व पटल पर आपसे, बढ़ा देश का मान।
युवा विवेकानंद है, भारत का अभिमान॥
युवा विवेकानन्द नें, दी अद्भुत पहचान।
युवा शक्ति की प्रेरणा, करे विश्व गुणगान॥
जाकर देश विदेश में, दिया यही संदेश।
धर्म, कर्म अध्यात्म का, मेरा भारत देश॥
अखिल विश्व में है किया, हिन्दी का उत्कर्ष।
हिंदी भाषा श्रेष्ठ है, है गौरव, है हर्ष॥
श्रेष्ठ हमारी सभ्यता, है संस्कृति महान।
श्रेष्ठ हमारे आचरण, श्रेष्ठ हमारा ज्ञान॥
लक्ष्य प्राप्ति हित अनवरत, करो सदा संघर्ष।
युवा शक्ति हो संघटित, खूब करे उत्कर्ष॥
आलोकित पथ को करे, भाव भरे अनमोल।
नमन विवेकानंद को, करे सभी दिल खोल॥
परम हंस से सीखकर,
बने विवेकानंद।
पाकर सौरभ प्रेरणा,
खिले हृदय मकरंद॥
-डॉ सत्यवान सौरभ

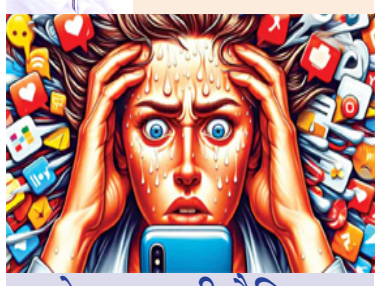

मोबाइल की हैसियत

कैसा जमाना आया आज
आदमी क्या से क्या हो गया
जिंदा इंसानों की कद्र नहीं
मोबाइल में इस कदर खो गया
समय नहीं है बार बार यह है बतलाता
मोबाइल पर ही अपना समय है बिताता
बर्बाद कर रहा समय इसके चक्कर में
खत्म कर दिया इसने सब रिश्ता नाता
लिखना भी भूल रहा इसी पर सब लिख जाता
घड़ी कोई नहीं डालता यही अब समय है बताता
गुणा भाग जमा घटाना सब तुरंत है कर देता
हर घर की जरूरत आज है मोबाइल बन जाता
छोटा हो या बड़ा सबको इसने है घुमाया
दिमाग कर दिया कमजोर जब से हाथ में है आया
अब तो जेब में पैसा रखने की भी जरूरत नहीं
इसी को है लोगों ने अपना बैंक बनाया
जिसने किया सही उपयोग उसका काम बनाया
किया जिसने दुरुपयोग उसको बहुत सताया
रिश्ते नाते यारी दोस्ती सब छीन ले गया
सोचो इसके आने से क्या खोया क्या पाया

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

हिंदी मेरे उर बसे

आन-बान सब शान है, और हमारा गर्व।
हिंदी से ही पर्व है, हिंदी सौरभ सर्व।।
हिंदी हृदय गान है, मृदु गुणों की खान।
आखर-आखर प्रेम है, शब्द- शब्द है ज्ञान।।
बिंदिया भारत भाल की, हिंदी एक पहचान।
सैर कराती विश्व की, बने किताबी यान।।
प्रीत प्रेम की भूमि है, हिंदी निज अभिमान।
मिला कहाँ किसको कहीं, बिन भाषा सम्मान।।
वन्दन, अभिनन्दन करे, ऐसा हो गुणगान।
ग्रंथन हिंदी का कर लो, तभी मिले सम्मान।।
हिंदी भाषा रस भरी, रखती अलग पहचान।
हिंदी वेद पुराण है, हिंदी हिन्दुस्तान।।
हिंदी की मैं दास हूँ, करूँ मैं इसकी बात।
हिंदी मेरे उर बसे, हिंदी हो जज्बात ।।
निज भाषा का धनी जो, वही सही धनवान।
अपनी भाषा सीख कर, बनता व्यक्ति महान।।
मौसम बदले रंग जब, तब बदले परिवेश।
हो हिंदीमय स्वयं जब, तभी बदलता देश।।
निज भाषा बिन ज्ञान का, होता कब उत्थान।
अपनी भाषा में रचे, सौरभ छंद सुजान।।
एक दिवस में क्यों बंधे, हिन्दी का अभियान।
रचे बसे हर पल रहे, हिन्दी हिन्दुस्तान।।
-प्रियंका सौरभ

गायब होती बेटियाँ: आखिर किसकी बन रहीं शिकार

हरियाणा के हिसार में लापता बेटी की खोज में परेशान एक पिता ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने सीएम के पास जाने से रोका तो दंपती ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री का काफि ला हिसार दौरे पर था। पिता ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे समय रहते रोक लिया। गीता कॉलोनी निवासी के अनुसार 29 सितंबर से उसकी 16 साल की बेटी लापता है। थाने में शिकायत देकर गुमशुदगी दर्ज करवा चुके हैं। उसने बताया कि वह गाड़ी चलाता है, बेटी नौवीं कक्षा तक पढ़ी है। बताया कि 29 सितंबर की सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर वह घर से निकली थी। लेकिन लगभग चार माह बाद भी बेटी नहीं मिली। आखिर कहाँ गायब हो जाती है देश की बेटियाँ? क्यों नहीं ढूँढ पाती बेटियों को हमारी पुलिस? इसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के तमाम दावों के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों में रुचि की कमी है।

भारत में बेटियों की सुरक्षा हमेशा से ही सबसे गंभीर मुद्दा रहा है। इसे लेकर कई कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके देश में लड़कियों के लापता होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार के अनुसार भारत में पिछले दो साल के बीच 15.13 लाख से ज्यादा लड़कियाँ और महिलाएँ लापता हुईं हैं। अब ये महिलाएँ कहाँ गई, इनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। इन लापता लड़कियों में 18 साल से कम और उससे ज्यादा दोनों उम्र की महिलाएँ शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर रोज 345 लड़कियाँ गायब हो जाती हैं। इनमें 170 लड़कियाँ किडनैप होती हैं, 172 लड़कियाँ लापता होती हैं और लगभग 3 लड़कियों की तस्करी कर दी जाती हैं। इनमें से कुछ लड़कियाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लापता, किडनैप और तस्करी की गई लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता। इस संख्या की गणना गुमशुदा महिलाओं और लड़कियों के सम्बंध में पुलिस स्टेशनों में दर्ज रिपोर्टों के आधार पर की है।

हालांकि सामाजिक कार्यकताओं का कहना है कि असल संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि कई परिवार सामाजिक कलंक समेत विभिन्न कारणों से लापता लड़कियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाएँ मध्य प्रदेश से लापता हुई हैं। एमपी के बाद लिस्ट में दूसरा स्थान बंगाल का है। इन राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली में भी लड़कियों और महिलाओं के गायब होने के कई मामले सामने आए हैं। आंकड़ों की मानें तो केंद्र शासित प्रदेशों में राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट चौंकाने वाली है। जो लड़कियाँ गायब होती हैं, उनमें से अधिकतर का पता नहीं चल पाता कि उनके साथ क्या हुआ है? वे कहाँ गई हैं? लापता होने के पीछे राज क्या हैं? 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली के निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया

था। इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई कठोर कानून बनाए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानूनों के बनाए जाने के बाद भी देश में महिलाओं की स्थितियाँ सुधरी हैं या महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कोई कमी नजर आई है भारत में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई कानून बनाए गए हैं।

देश में हो रहे यौन अपराध को रोकने के लिए पुराने कानूनों में संशोधन भी किया गया और उसे कठोर भी बनाया गया है। इसके अलावा देश में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप की घटना में दोषी को मृत्युदंड सहित कई कठोर दंडात्मक प्रावधान भी तय किए गए हैं। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं, जिसमें यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 शामिल है। इसके अलावा, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित और भी अधिक कठोर दंड प्रावधानों को-को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में बलात्कार के मामलों में दो महीने में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने और अगले दो महीने में सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया गया है। सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली शुरू की है, जो सभी आपात स्थितियों के लिए एक अखिल भारतीय, एकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर (112) आधारित प्रणाली प्रदान करती है, जिसमें संकटग्रस्त स्थान पर फील्ड संसाधनों को कंप्यूटर सहायता से भेजा जाता है।

स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में आठ शहरों-अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में सुरक्षित शहर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। फिर भी भारत में महिलाएँ आज से 10 साल पहले भी यौन अपराधियों का शिकार बनती रही है और आज भी हालात कुछ बहुत ऐसे ही हैं। देश में छेड़छाड़, अपहरण और दुष्कर्म जैसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार के तमाम दावों के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों में रुचि की कमी है। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर महिलाओं और लड़कियों को कुछ कानूनों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इन कानूनों में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, महिला सुरक्षा कानून, पॉक्सो एक्ट कानून शामिल है ।

डॉ. सत्यवान सौरभ,

खतरनांक वायरस की दस्तक

भारत में कर्नाटक गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुछ बच्चों में नये वायरस के मामले मिल चुके हैं जिसके बाद भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। कमजोर प्रतिरक्षा वाले रोगियों में यह संक्रमण निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और उनमें मौत का जोखिम बढ़ जाता है।

वर्ष 2020 में चीन से शुरू होकर कोरोना ने पूरी दुनिया में जो दहशत मचाई, उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोरोना महामारी के भयावह दौर में दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए, लाखों परिवार उजड़ गए, अनेक बच्चे अनाथ हो गए। अभी तक कोरोना का खौफ बरकरार है और कोरोना की शुरूआत के पांच साल बाद अब चीन से ही एक और ऐसे ही खतरनाक वायरस की दस्तक की खबरें दुनिया के सामने आ रही हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।

भारत में कर्नाटक गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुछ बच्चों में नये वायरस के मामले मिल चुके हैं जिसके बाद भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। कमजोर प्रतिरक्षा वाले रोगियों में यह संक्रमण निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और उनमें मौत का जोखिम बढ़ जाता है। हाल के दिनों में कई रिपोर्टों में बताया जा चुका है कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) नामक वायरस ने इन दिनों चीन में दहशत फैला रखी है। इस खतरनाक वायरस के कारण बड़ी संख्या में मरीज मर रहे हैं लेकिन कोविड की ही भांति चीन द्वारा इसे लेकर भी लीपापोती की जा रही है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

सूच्य हो कि उत्तर चीन के प्रांतों में 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों में एचएमपीवी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खचाखच भरे अस्पताल और श्मशानों में बेतहाशा भीड़ इस संकट के कोरोना जैसा या उससे भी बदतर होने की पुष्टि कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर सार्सझसीओवी-2 (कोविड-19)' नामक एक्स हैंड़ल द्वारा पोस्ट में लिखा गया है कि चीन एचएमपीवी, इन्फ्लूएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरस के मामलों में उछाल का सामना कर रहा है और वहां के अस्पताल निमोनिया और ह्यव्हाइट लंग' के मामलों से खासे परेशान हैं। एचएमपीवी वायरस का प्रकोप भी सबसे पहले चीन में ही शुरू हुआ है। दरअसल, बर्ड फ्लू से लेकर सार्स और कोविड तक सभी महासंहारक वायरल प्रकोपों की उत्पत्ति चीन से ही होती रही है। चूंकि सभी वायरस चीन में ही पैदा होते रहे हैं, इसलिए ऐसे वायरस हमलों को लेकर दुनिया में चीन को लेकर संदेह का माहौल बना हुआ है कि कहीं कोविड-19 के बाद खतरनाक होता एचएमपीवी भी चीन की जैविक प्रयोगशालाओं में रची जा रही साजिश तो नहीं है। हालांकि डच शोधकर्ताओं ने 2001 में सबसे पहले श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित बच्चों में इस वायरस की खोज की थी और हर साल कई देशों में इसके कुछ मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन चीन में जिस तरह इस वायरस ने आतंक मचाया हुआ है, ऐसे में भारत ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थिति पर नजर रखे हुए है तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल का कहना है कि बताया गया है कि चीन में मेटान्यूमोवायरस वायरस का एक आउटब्रेक है, जो गंभीर है। हालांकि उनका कहना है कि हमें नहीं लगता कि भारत में किसी गंभीर स्थिति की आशंका है।

दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुण गुप्ता का कहना है कि भारत में इस वायरस के कारण बीमारी बढ़ने की अभी आशंका नहीं है। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार, एचएमपीवी सभी उम्र के लोगों में अपर और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण बन सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने-छींकने से निकलने वाले स्राव या नजदीकी संपर्क जैसे हाथ मिलाने से भी यह वायरस फैलता है। एचएमपीवी वायरस न्यूमोवायराइड और मेटान्यूमो वायरस जीनस का हिस्सा है जो सिंगलझस्ट्रैंड्रेड नेगेटिव-सेंस आरएनए वायरस है।

चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार- इस वायरस का संक्रमणकाल तीन से पांच दिन होता है। इसके संक्रमण से रोग-प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होती है। एचएमपीवी कोरोना की ही भांति श्वसन पथ को संक्रमित करता है, हालांकि कोरोना के मुकाबले इसके कारण ऊपरी और निचलेङ्क दोनों श्वसन पथ में संक्रमण का खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कम पहचाना वायरस है, लेकिन दुनिया भर में मौसमी श्वसन बीमारियों में योगदान कर रहा है।

एचएमपीवी में कोरोना ही भांति फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं। इससे बचाव के उपायों में हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोना, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक ढंकना, संक्रमितों से दूरी बनाना, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद लेना, फ्लू के टीके लगवाना इत्यादि शामिल हैं।

आजादी के 74 साल बाद भी राजधानी दिल्ली सहित महानगरों में ही नहीं बल्कि हमारे दूर-दराज के जिलों में राज्य सरकारें अपना कामकाज अंग्रेजी में करती हैं। हिन्दी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही हमारी राजभाषा भी है, यह हमारे अस्तित्व एवं अस्मिता की भी प्रतीक है, यह हमारी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति की भी प्रतीक है।

वैश्विक पटल पर बढ़ती हिन्दी की धाक

विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी, 2006 को मनाया गया था। आज हिन्दी विश्व की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली तीसरी भाषा है, विश्व में हिन्दी की प्रतिष्ठा एवं प्रयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश में उसकी उपेक्षा एक बड़ा प्रश्न है। सच्चाई तो यह है कि देश में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, वह स्थान एवं सम्मान अंग्रेजी को मिल रहा है। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की सहायता जरूर ली जाए लेकिन तकनीकी एवं कानून की पढ़ाई के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आज भी भारतीय न्यायालयों में अंग्रेजी में ही कामकाज होना राष्ट्रीयता कमजोर कर रहा है। राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय प्रतीकों की उपेक्षा एक ऐसा प्रदूषण है, एक ऐसा अंधेरा है जिससे ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। राष्ट्र-भाषा को लेकर छाई धुंध को मिटाने के लिये कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने ही होंगे।

कितने दुख की बात है कि आजादी के 74 साल बाद भी राजधानी दिल्ली सहित महानगरों में ही नहीं बल्कि हमारे दूर-दराज के जिलों में राज्य सरकारें अपना कामकाज अंग्रेजी में करती हैं। हिन्दी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही हमारी राजभाषा भी है, यह हमारे अस्तित्व एवं अस्मिता की भी प्रतीक है, यह हमारी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति की भी प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद ही हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रचारित-प्रसारित करने के लिए 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा बनने के बाद हिन्दी ने विभिन्न राज्यों के कामकाज में आपसी लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का अभिनव कार्य किया है। लेकिन अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण आज भी हिन्दी भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं है, जो होना चाहिए। विशेषतः अदालतों में आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व कायम रहना, एक बड़ा प्रश्न है। देश की सभी निचली अदालतों में संपूर्ण कामकाज हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होता है, किंतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यही काम केवल अंग्रेजी में होता है। यहां तक कि जो न्यायाधीश हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं जानते हैं वे भी अपीलीय मामलों की सुनवाई में दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद कराते हैं।

आमजन के लिए न्याय की भाषा कौन-सी हो, इसका सबक भारत और भारतीय न्यायालयों को अबू धाबी से लेने की जरूरत है। संयुक्त अरब अमीरात यानि दुबई और अबू धाबी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। इसका मकसद हिंदी भाषी लोगों को मुकदमे की प्रक्रिया, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सीखने में मदद करना है। न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। अमीरात की जनसंख्या 90 लाख है। उसमें 26 लाख भारतीय हैं, इन भारतीयों में कई पढ़े-लिखे और धनाढ्य लोग भी हैं लेकिन ज्यादातर मजदूर और कम पढ़े-लिखे लोग हैं। इन लोगों के लिए अरबी और अंग्रेजी के सहारे न्याय पाना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि अदालत में वकील क्या बहस कर रहे हैं और जजों ने जो फैसला दिया है, उसके तथ्य और तर्क क्या हैं? ज्वलंत प्रश्न है कि विदेशों में बसे भारतीयों की इस तकलीफ का ध्यान रखने का निर्णय लिया गया है तो भारत में ऐसे निर्णय क्यों नहीं लिये जाते? प्रश्न यह भी है कि विदेशों में ही क्यों बढ़ रही है हिन्दी की ताकत? झकझोरने वाला प्रश्न यह भी है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी को आजादी के 72 वर्ष बीत जाने पर भी अपने ही देश में क्यों घोर उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है? हिन्दी की उपेक्षा राष्ट्रीय शर्म का विषय है, जबकि विश्व में हिन्दी की ताकत बढ़ रही है। भारत सरकार के प्रयत्नों से हिन्दी को विश्वस्तर पर प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, यह सराहनीय बात है। लेकिन भारत में उसकी उपेक्षा कब तक होती रहेगी, यह प्रश्न भी सरकार एवं आमजन के लिये सोचनीय होना चाहिए।

हिन्दी को कानून की भाषा बनाने का जो काम भारत में सबसे पहले होना चाहिए था, वह काम संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय तो अभी भी अंग्रेजी में ही सारे काम-काज के लिये अड़ा हुआ है। वहां मुकदमों की बहस अंग्रेजी में ही होती है। जहां बहस अंग्रेजी में होती है, वहां फैसले भी अंग्रेजी में ही आते हैं। अभी सुना है कि उनके हिंदी अनुवाद की बात चल रही है। बात केवल कानून के सर्वोच्च संस्थान की ही नहीं है, बल्कि समस्त सरकारी कामकाज भी अंग्रेजी में ही होता है, उच्च शिक्षा भी अंग्रेजी में ही दी जा रही है, यहां तक प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा में भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है, कैसे हम अपनी भाषा को प्राथमिकता देंगे? कब भारत के भाग्य निमार्ता हिन्दी को जनभाषा, राजकाज की भाषा एवं कानून की भाषा का दर्जा देकर बधाई के पात्र बनेंगे? भारत एक है, संविधान एक है। लोकसभा एक है। सेना एक है। मुद्रा एक है। राष्ट्रीय ध्वज एक है। लेकिन इन सबके अतिरिक्त बहुत कुछ और है जो भी एक होना चाहिए। बात चाहे राष्ट्र भाषा की हो या राष्ट्र गान या राष्ट्र गीत- इन सबको भी समूचे राष्ट्र में सम्मान एवं स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार को चाहिए कि वह ऐसे आदेश जारी करे जिससे सरकार के सारे अंदरूनी कामकाज भी हिन्दी में होने लगें और अंग्रेजी से मुक्ति की दिशा सुनिश्चित हो जाये। अगर ऐसा होता है तो यह राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अनुकरणीय एवं सराहनीय पहल होगी। ऐसा होने से महात्मा गांधी, गुरु गोलवलकर और डॉ. राममनोहर लोहिया का सपना साकार हो सकेगा।

दुनिया में जितने भी देश महाशक्ति के दर्जे में आते हैं, उनकी अदालतों में मातृभाषा चलती है। यूरोपीय देशों में जैसे-जैसे शिक्षा व संपन्नता बढ़ी, वैसे-वैसे राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रखर होता चला गया। रूस, चीन, जापान, वियतनाम और क्यूबा में भी मातृभाषाओं का प्रयोग होता है। लेकिन भारत और भारतीय अदालतें कोई सबक या प्रेरणा लिए बिना अंग्रेजी को स्वतंत्रता के 74 साल बाद भी ढोती चली आ रही हैं। अदालतों को अब इस भाषायी रंगभेद की दासता से मुक्त होने की जरूरत है। नेता हो या जनता- हिन्दी की यह दुर्दशा एवं उपेक्षा सोचनीय है। अत्यन्त सोचनीय है। खतरे की स्थिति तक सोचनीय है कि आज का तथाकथित नेतृत्व दोहरे चरित्र वाला, दोहरे मापदण्ड वाला बना हुआ है। उसने कई मुखौटे एकत्रित कर रखे हैं और अपनी सुविधा के मुताबिक बदल लेता है, यह भयानक स्थिति है। इसी कारण हिन्दी को आज भी दोयम दर्जा हासिल है। हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिये नरेन्द्र मोदी एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के प्रयत्नों को राष्ट्र सदा स्मरणीय रखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर न केवल हिन्दी को गौरवान्वित किया बल्कि देश के हर नागरिक का सीना चौड़ा किया। भारत और अन्य देशों में 70 करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। पाकिस्तान की तो अधिकांश आबादी हिंदी बोलती व समझती है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान में भी लाखों लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद जैसे देश तो हिंदी भाषियों द्वारा ही बसाए गये हैं। हिन्दी का हर दृष्टि से इतना महत्व होते हुए भी भारत में प्रत्येक स्तर पर इसकी इतनी उपेक्षा क्यों? शेक्सपीयर ने कहा था-दुर्बलता! तेरा नाम स्त्री है। पर आज शेक्सपीयर होता तो आम भारतीय एवं सरकारों के द्वारा हो रही हिन्दी की उपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में कहता-दुर्बलता! तेरा नाम भारतीय जनता एवं शासन व्यवस्था है। क्योंकि दुनिया में हिन्दी का वर्चस्व बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होना, इन्हीं विरोधाभासी एवं विडम्बनापूर्ण परिस्थितियों को ही दर्शाता है। -ललित गर्ग

नया संकट : अगला दशक कहीं बुजुर्गों का दशक ना हो जाए

दरअसल, दुनिया के देशों में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि कामकाजी युवाओं की संख्या कम से कम होती जाएगी। यह दुनिया के देशों के सामने बड़ा संकट दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि चीन सहित विभिन्न देश अब आबादी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने लगे हैं। एक या दो बच्चों की नीति को त्यागकर तीन बच्चों तक की नीति को अपनाने लगे हैं। दक्षिण कोरिया में माता-पिता को बच्चे के जन्म से लेकर सात वर्ष का होने तक विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन ओर सहायता योजना में 35 से 50 युआन तक दे रहे हैं। इसी तरह से यूरोप के कई देश अपने नागरिकों को प्रोत्साहित करने की कई कार्यक्रमों का संचालन कर प्रोत्साहित करने लगे हैं।

प्रजनन दर कम होने के पीछे जहां दुनिया के देशों की आबादी को नियंत्रित करने की नीति रही वहीं अब जनसंख्या नियंत्रित होने के कई कारणों में से एक कारण आधुनिक जीवन शैली, रहन-सहन, मंहगाई, शिक्षा स्वास्थ्य व आवास जैसी समस्याएं आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही शैक्षिक स्तर बढ़ने और सोच में बदलाव भी बड़ा कारण है। देखा जाए तो अब भारत सहित दुनिया के देशों में बाल विवाह में कमी, आत्मनिर्भर होने पर विवाह बंधन में बंधने की प्रवृति, महिलाओं में भी शादी के प्रति अनिच्छा या फिर अधिक उम्र में शादी, इसके मुख्य कारण हैं। एक सर्वे के अनुसार हालांकि यह अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है कि आज की पढ़ी-लिखी महिलाएं शादी तो करना चाहती हैं पर बच्चे पैदा करने, उनके लालन-पालन और घर-गृहस्थी को बोझ मानने की मानसिकता भी एक कारण होती जा रही है। इस सबसे अलग दुनिया के किसी भी कोने को ले लें अब हालात यह हो गए हैं कि आधुनिकता और जीवन स्तर के चलते कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहन-सहन का खर्च बढ़ गया है। एक बड़ा कारण यह है कि लोग परिवार को सीमित रखने व देरी से शादी लिविंग स्टैण्डर्ड के कारण प्रमुखता देने लगे हैं।

जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उससे दुनिया के देश चिंतित

लैसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक दुनिया के देशों में प्रजनन दर 1.6 रह जाएगी। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, देशों के बीच परस्पर शक्ति संतुलन, खाद्य, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि प्रभावित होंगे।

हो गए हैं। एक बच्चे की नीति को तो करीब-करीब सभी देश त्यागने ही लगे हैं क्योंकि यह लगने लगा है कि अगला दशक कहीं बुजुर्गों का दशक ना हो जाए। सरकारों के सामने इससे गंभीर संकट के हालात इस मायने में हो जाएंगे कि उत्पादक जेनरेशन यानी युवा कम होते जाएंगे और बुजुर्ग अधिक हो जाएंगे। इससे सामाजिक ताने-बाने के साथ उत्पादकता सहित अनेक विषमताएं सामने आने लगेगी। आज क्रोसिया, ग्रीस, इटली, मालटा, पुर्तगाल, स्लोवानिया आदि दक्षिण यूरोप के देशों में 65 साल से अधिक की आबादी 21 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जापान में 29 प्रतिशत तो मोनाको में 36 प्रतिशत आबादी 65 साल से अधिक के नागरिकों की हो गई है।

इसमें दो राय नहीं कि स्वास्थ्य बेहतरी के चलते औसत उम्र में बढ़ोतरी हुई है। यहां बुजुर्ग आबादी को लेकर कोई नकारात्मक सोच नहीं है पर जिस तरह से प्रजनन दर कम हो रही है और आने वाले समय में संकट दिखाई दे रहा है उसे लेकर चिंता है। इस चिंता को सरकारों, चिंतकों, मनोविज्ञानियों सहित समाज के सभी वर्गों को विचार करना होगा ताकि समय रहते संतुलन बनाए रखा जा सके।

दुनिया के देशों के सामने जनसंख्या नीति के नकारात्मक प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। दक्षिण कोरिया, चीन, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल सहित दुनिया के अनेक देश घटती जन्म दर से दो- चार हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 124 देशों में जनसंख्या दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर से विकसित देशों में जनसंख्या दर में तेजी से गिरावट आ रही है। विषेषज्ञों की मानें तो यही हालात रहे तो दक्षिण कोरिया और सर्बिया आदि के सामने तो 2100 तक अस्तित्व का संकट आ सकता है। 2100 तक दक्षिण कोरिया की आबादी 5.1 करोड़ से घटकर इसकी तिहाई रह जाएगी। खास बात यह कि बुजुर्गों की आबादी तो बढ़ेगी पर युवाओं की आबादी बहुत कम रह जाएगी।

लैसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक दुनिया के देशों में प्रजनन दर 1.6 रह जाएगी। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, देशों के बीच परस्पर शक्ति संतुलन, खाद्य, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि प्रभावित होंगे। दरअसल 1950 में दुनिया के देशों में औसत प्रजनन दर 5 बच्चे थी जो 2021 आते आते 2.1 रह गई है। विषेषज्ञों की मानें तो यह प्रजनन दर 2050 तक घटकर 1.8 रह जाएगी और 2100 तक 1.6 रह जाएगी। इससे तेजी से आबादी तो नियंत्रित हो जाएगी पर इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि पश्चिमी व पूर्वी उप सहारा क्षेत्र अफ्रीका के देशों में प्रजनन दर में उतनी गिरावट नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मानव जाति के लिए 2.1 प्रजनन दर होना जरूरी है। चीन, कोरिया सहित अनेक देशों में यह दर कम होती जा रही है। यही कारण है कि चीन सहित अनेक देशों ने अपनी जनसंख्या नीति में परिवर्तन किया है। अब चीन कोरिया सहित अनेक देश अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे हैं। चीन में एक बच्चे की नीति के कारण जनसंख्या तो नियंत्रित हो गई पर उस के परिणाम खासतौर से युवा पीढ़ी के कम होने के कारण दो बच्चों और फिर उसमें भी सफलता नहीं मिलने पर तीन बच्चों की नीति लागू की गई है।

घूँघट की बगावत

12 जनवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

6

हाशिए पर खिसकती बेघरों के लिए आवासीय योजनाएं

मौसम की अति के चलते असमय होने वाली ये मौतें हमारे उस भारत की नग्न सच्चाइयां हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह तेजी से विकास कर रहा है और जल्द ही दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। ये सच्चाइयां सिर्फ हमारी सरकारों के हवा-हवाई कार्यक्रमों और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाने जैसे गुलाबी दावों की ही खिल्ली नहीं उड़ातीं, बल्कि व्यवस्था पर काबिज लोगों की नालायकी और संवेदनहीनता को भी उजागर करती हैं। वैसे, सर्दी हमारे नियमित मौसम चक्र का ही हिस्सा है। कड़ाके की सर्दी इसका हल्का सा विचलन भर है। सर्दी और भीषण सर्दी अंत में हमें कई तरह से फायदे ही पहुंचाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि कड़ाके की सर्दी हमें आश्वस्त करती है कि ग्लोबल वामिंग उतनी सन्निकट नहीं है, जितना कि अक्सर हम मान बैठते हैं। ज्यादातर भारतीय इस मायने में खुशनसीब हैं कि उन्हें मौसम की विविधताएं देखने को मिलती हैं। अन्यथा दुनिया में ऐसे कम ही इलाके हैं, जहां हर मौसम का मजा लिया जा सके। हर मौसम अपने रौद्र रूप में भी सुंदर होता है बशर्ते उसकी मार से लोगों को बचाने के इंतजामात हो। दुनिया में संभवतः भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जहां हर मौसम की अति होने पर लोगों के मरने की खबरें आने लगती हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि लोग मौसम की अति से नहीं मरते हैं, वे मरते हैं अपनी गरीबी से, अपनी साधनहीनता से और व्यवस्था तंत्र की नाकामी या लापरवाही की वजह से। यूरोप के देशों में सरकारें मौसम की अति का मुकाबला करने के चाक-चौबंद इंतजाम करती हैं, इसलिए वहां लोग हर मौसम का तरह-तरह से लुत्फ उठाते हैं। हमारे देश में भी खाया-अघाया तबका ऐसा ही करता है, जिसके पास हर मौसम की अति का सामना करने और उसका लुत्फ उठाने के पर्याप्त साधन हैं।

नया साल शुरू हो चुका है, और उससे पहले शुरू हो गई कंपकंपा देने वाली सर्दी। इस समय भी देश के विभिन्न इलाकों में शीत लहर कहर बरपा रही है जिससे हर साल की तरह देश के विभिन्न इलाकों से लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। अब तक डेढ़ सौ से ज्यादा लोग सर्दी की ठिठुरन से मौत की नींद सो चुके हैं। वैसे इस तरह की खबरें आना कोई नई बात नहीं है। कहीं भूख और कुपोषण से होने वाली मौतें तो कहीं गरीबी और कर्ज के बोझ से त्रस्त किसानों और छोटे कारोबारियों की खुदकुशी के जारी सिलसिले के बीच हर साल ही सर्दी की ठिठुरन, गरम लू के थपेड़ों और बारिश-बाढ़ से भी लोग मरते ही रहते हैं। भारत के ज्यादातर हिस्सों में यूरोप जैसी ठंड नहीं पड़ती लेकिन हमारे यहां जब हिमालय परिवार की पहाड़ियों पर गिरने वाली बर्फ से मैदानी इलाकों में शीत लहर चलती है तो देश के विभिन्न इलाकों में सर्दी की ठिठुरन से होने वाली मौतों के आंकड़े.आने लगते हैं। हकीकत यह है कि अगर समूचे भारत के आंकड़े.इकट्ठे किए जाएं तो हर साल सर्दी से मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंचती है। ज्यादातर मौतें बड़े शहरों और महानगरों में होती हैं। जो मरते हैं, उनमें से ज्यादातर बेघर होते हैं। ऐसे लोग काम की तलाश में दूरदराज के इलाकों से बड़े शहरों या महानगरों में जाते हैं ताकि मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार के जिंदा रह सकने लायक कुछ कमा सकें। इनमें कोई साइकिल रिक्शा चलाते हैं,कोई रेस्तरांओं और ढाबों में काम करते हैं, तो कोई किसी और काम में लग जाते हैं। लेकिन चूंकि ऐसे लोगों के पास रहने के लिए अपना कोई ठिकाना नहीं होता है, इसलिए खुले आसमान के नीचे रात गुजारना उनकी मजबूरी होती है। गरमी या दूसरे मौसम में तो किसी तरह उनकी रातें कट जाती हैं, लेकिन कड़ाके की शीत लहर में एक रात भी सुरक्षित बीत जाने पर वे असीम राहत महसूस करते हैं। अगर वे सर्दीजनित किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि अपना इलाज करा सकें। सर्दी के दिनों में ऐसे जानलेवा हालात का सामना करने वाले लोगों की तादाद लाखों में होती है। सवाल यह है कि अगर इन लोगों के सामने साधनहीनता एक लाचारी है, तो कल्याणकारी मूल्यों पर चलने का दावा करने वाली सरकारों की क्या कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? दरअसल, शहरी और अर्द्धशहरी इलाकों में मौसम की मार से लोगों के मरने के पीछे सबसे बड़ी वजह है शहरी नियोजन में सरकारी तंत्र की अदूरदर्शिता। जब से आवासीय कॉलोनियों की बसावट के मामले में विकास प्राधिकरणों और गृह निर्माण मंडलों की बजाय निजी भवन निर्माताओं और कॉलोनाइजरों का दखल बढ़ा है, तब से रोज कमा कर रोज खाने वालों और बेघर लोगों के लिए आवासीय योजनाएं हाशिए पर खिसकती गई हैं। करोड़ों लोग आज भी फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर या टाट और प्लास्टिक आदि से बनी झोपड़ियों में रात बिताते हैं। बहुत से लोगों के पास तो पहनने को गरम कपड़े या ओढ़ने को रजाई-कंबल तो दूर तापने को सूखी लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे लोगों को मौसम की मार से बचाने के लिए अदालतें हर साल सरकारों और स्थानीय निकायों को लताड़ती रहती हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की मोटी चमड़ी पर ऐसी लताड़ों का कोई असर नहीं होता है। शीत लहर, बाढ़ और भीषण गर्मी जैसी प्राकृतिक आपदाएं कोई नई परिघटना नहीं हैं। ये तो पहले से आती रही हैं, और आगे भी आती रहेंगी। इन्हें रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है, तो इनसे होने वाली जान-माल की तबाही को, जो सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की ईमानदार इच्छाशक्ति से ही संभव है। ताजा शीत लहर और उससे होने वाली मौतें हमें बता रही हैं कि जब मौसम के हल्के से विचलन का सामना करने तक की हमारी तैयारी नहीं है, और हमारी व्यवस्थाएं पंगु बनी हुई हैं, तो जब ग्लोबल वामिंग जैसी चुनौती हमारे सामने होगी तो उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे?

जब से आवासीय कॉलोनियों की बसावट के मामले में विकास प्राधिकरणों और गृह निर्माण मंडलों की बजाय निजी भवन निर्माताओं और कॉलोनाइजरों का दखल बढ़ा है, तब से रोज कमा कर रोज खाने वालों और बेघर लोगों के लिए आवासीय योजनाएं हाशिए पर खिसकती गई हैं। करोड़ों लोग आज भी फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर या टाट और प्लास्टिक आदि से बनी झोपड़ियों में रात बिताते हैं। बहुत से लोगों के पास तो पहनने को गरम कपड़े या ओढ़ने को रजाई-कंबल तो दूर तापने को सूखी लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं हैं।

ऑनलाइन क्लासेस और लॉकडाउन ने बनाया बच्चों को इंटरनेट का आदी

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का हर तीसरा व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया आज जिस तरह आपत्तिजनक सामग्री परोसने का जरिया बन गया है इसका बहुत ही गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है।

आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले देशों में है।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का हर तीसरा व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया आज जिस तरह आपत्तिजनक सामग्री परोसने का जरिया बन गया है इसका बहुत ही गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया उपयोग पर पाबंदी के बाद भारत सरकार द्वारा भी उठाया गया कदम सराहनीय है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से अश्लील सामग्री हिंसक वीडियो एवं वयस्क सामग्री परोसे जा रहे हैं जिसके संपर्क में आकर बच्चे गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। बिना पैरेंट के कंट्रोल के सोशल मीडिया के उपयोग द्वारा बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार भी हो सकते हैं जो बच्चों में डर और मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। बच्चों में बाहरी दुनिया और सामाजिक समझ नहीं होती है। अगर बच्चे बिना बड़ों की निगरानी के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी साझा कर सकते हैं, जो बच्चों की सुरक्षा खतरे में डाल सकती है। सोशल मीडिया के अत्याधिक उपयोग से बच्चो अधिक समय बिताना बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है साथ ही बच्चे पढ़ाई में अरुचि दिखा रहे हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी बहुत ही अच्छी पहल है। ऐसा करने से माता-पिता की जागरूकता बढ़ेगी और वो बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रख पाएंगे। इस नियम से बच्चों द्वारा सोशल मीडिया उपयोग की समय सीमा सीमित हो जाएगी, जिससे बच्चे अन्य गतिविधियों में भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। निश्चित रूप से यह अधिनियम देश को एक सकारात्मक परिणाम देगा।

भारतीय संसद ने अगस्त 2023 'डेटा संरक्षण अधिनियम' पारित किया। जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा करना है। 3 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने इस नियम से संबंधित प्रारंभिक दस्तावेज जारी किया। इस मसौदे में सबसे अच्छी पहल बच्चों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोग करने पर नियंत्रण शामिल हैं। कोविड १९ के बाद ऑनलाइन क्लास और लॉकडाउन के कारण बच्चों में इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है जिससे उन्हें सोशल मीडिया के गलत प्रभावों से बचाने की आवश्यकता हैं।

भारत 2026 तक एक बड़ा खिलाड़ी बन कर उभर सकता है

आईएमएफ के मुताबिक 2025 में ही भारत जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ देगा। जबकि एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक, ऐसा निकट भविष्य में होगा जरूर, पर 2030 से पहले नहीं। अर्थशास्त्रियों के बीच आज इस बात पर तकरीबन एक तरह की सहमति है कि बीते पांच वर्षों में भारत आर्थिक क्षमता के मामले में लगातार आगे बढ़ा है। आलम यह है कि भारत डॉलर की जगह अब अपने रुपए का उपयोग करके 27 देशों के साथ व्यापार करता है जो वैश्विक व्यापार में इसके बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। वैश्विक डिजिटल लेनदेन में भी देश की हिस्सेदारी 46 फीसद है।

एक अध्ययन के मुताबिक सरकारी और निजी तौर पर जिस देश के साथ व्यापारिक साझीदारी को लेकर दिलचस्पी आज सबसे ज्यादा है, वह भारत है। अलबत्ता इसमें कहीं दो राय नहीं कि इन वर्षों में भारत की आर्थिक हैसियत को नीतिगत समर्थन जितना नहीं मिला है उससे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि और युवा आबादी जैसे कारक कारगर हुए हैं। रुपए की बढ़ी साख के साथ बदल रही स्थितियों के बीच एक अनुमान इस बात को भी लेकर लगाया जा रहा है कि यूएस डॉलर की विश्व व्यापार में हैसियत को बनाए रखने के लिए ट्रंप कोई बड़ी और आक्रामक नीतिगत पहल कर सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर इस पहल से जहां रुपये की बढ़ती ताकत को रोकने के प्रयास होंगे वहीं अमेरिकी डॉलर में लेनदेन को लेकर कूटनीतिक प्रलोभन भी परोसे जा सकते हैं।

21वीं सदी का दूसरा दशक अपने आगाज से वैश्विक घटनाक्रम को एक ऐसे सीध में लेकर बढ़ रहा है जो पूरी तरह अप्रत्याशित है। इस पूरे दौर को पहली शिनाख्त कोविड काल के रूप में मिली वहीं अब नये ग्लोबल ऑर्डर तय होने की बात की जा रही है। यह ग्लोबल आर्डर जहां अमेरिका के वैश्विक चौधराहट को नये सिरे से तय कर रहा है वहीं इस बीच बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे भारत जैसे देश के अमेरिका के साथ चल रहे संबंध का भी उत्तरकाल शुरू हो रहा है। टाइमिंग और देशकाल की साझी और नई शब्दावली में इस उत्तरकाल को ट्रंप 2.0 और मोदी 3.0 की नीतियां और घोषणाएं शक्ल देने जा रही हैं। ॥

ट्रंप 2.0 और मोदी 3.0 का तारीखी महत्व इस लिहाज से बड़ा है कि इन दो विश्व नेताओं के कार्यकाल में विश्व की चोटी की अर्थव्यवस्थाओं के शीर्ष देशों के नाम में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। इस दौरान अमेरिका जरूर चोटी पर बना रहेगा पर भारत जल्द जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दिलचस्प यह कि इस बात की सुगबुगाहट भारत में बाद में, जापान में पहले शुरू हुई।

इस बाबत जापान टाइम्स ने कुछ अर्थशस्त्रियों के साथ चर्चा के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। जिन लोगों के विश्लेषण को इसमें अहमियत दी गई है उनमें कैपिटल इकोनॉमिक्स के एशियाझप्रशांत प्रमुख मार्सेल थिएलियंट भी शामिल हैं। रिपोर्ट में थिएलियंट ने अपने अनुमान को लेकर कहा है कि भारत जीडीपी में 2026 तक जापान को पछाड़ देगा। इस बारे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) दो कदम और आगे है। तमाम तरह के पूवार्नुमानों के बीच इन आशंकाओं से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता है कि 2025 में दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। जाहिर है कि भारत-अमेरिका संबंध का नया दौर भी इन्हीं आशंकाओं के बीच आकार लेगा। क्योंकि जो दबाव पूरी दुनिया पर है वह अमेरिका पर भी बल्कि कई मामलों में ज्यादा भी है। ट्रंप 2.0 के साथ आरंभ हो रहे नये दौर को लेकर जो जिस तरह के संकेत हैं उसमें एक बड़ी आशंका इस बात को लेकर है कि चीन समेत दुनिया के कई देशों पर अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है। इससे स्वाभाविक तौर वैश्विक व्यापार का मौजूदा स्वरूप प्रभावित होगा और आर्थिक दबाव की नई स्थितियां पैदा होंगी। यूक्रेन और मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव से भी आर्थिक मंदी को लेकर चिंता बढ़ी है। इस स्थिति से खासतौर पर जर्मनी और खंस जैसी प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में संकट पैदा हो सकता है। गौरतलब है कि २०२४ में तकरीबन आधी दुनिया में चुनाव हुए और जिन सरकारों ने सत्ता संभाली या जिन नेताओं को चुना गया, उनके कार्यों का असर इस वर्ष स्पष्टता के साथ नजर आएगा। सत्ता संभालने से पहले ही नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह चीन के साथ-साथ कनाडा एवं मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ाने का एलान किया है उससे दुनियाभर में हलचल मचना लाजिमी है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट' की नीति पर आगे बढ़ते हुए चीनी सामानों पर किसी भी अतिरिक्त टैरिफ के इतर 10 फीसद तथा कनाडा एवं मैक्सिको पर 25 फीसद टैरिफ लगाने का एलान किया है। अगर अमेरिका चीन पर दस फीसद अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाता है तो निसंदेह इससे चीन का नुकसान तय है। इसीलिए चीन ने ट्रंप के इस ऐलान को अपने खिलाफ एक नया व्यापार युद्ध करार दिया है। साफ है कि दोनों देश आने वाले दिनों में ट्रेड वार से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल, ट्रंप किसी भी सूरत में चीन पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। याद होगा ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी उनके चीन से रिश्ते बेहतर नहीं थे। कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने चीन पर कड़ी टिप्पणी की थी।

अलबत्ता अगर अमेरिका चीन के विकास और तकनीकी प्रगति के लिए खर्च को सीमित करने के लिए चीनी वस्तुओं पर कड़ा निर्यात नियंत्रण और टैरिफ लगाता है तो इससे ग्लोबल चेन प्रभावित होनी तय है। ऐसे में ग्लोबल आपूर्ति के निमित्त भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर सकता है। माना जा रहा है कि चीन पर टैरिफ बढ़ने से चीनी उत्पाद अमेरिकी बाजार में काफी महंगे हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने का सुनहरा मौका होगा। भारत इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से लेकर लेदर, मशीनरी, खिलौना जैसे उत्पादों के जरिए अमेरिकी बाजार में अपना दबदबा बना सकता है। एक आकलन है कि टैरिफ बढ़ने से चीन में उत्पादन करने वाली अमेरिका, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कंपनियों के लिए अमेरिका में एक्सपोर्ट करना फिर घाटे का सौदा होगा। ऐसे में यह कंपनियां चीन की जगह किसी अन्य देश को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाने का फैसला ले सकती हैं।

एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू करने का हो विचार

कृषि कानूनों से किसानों में यह बात घर कर गई कि इनके जरिये सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों का मोहताज बनाकर छोड़ देगी, जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिये कृषि क्षेत्र में नए निवेश के अवसर पैदा होंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

कृषि संकट एक वैश्विक घटना है। कई देशों में छोटे किसानों को संसाधनों तक पहुंच की कमी, कम पैदावार, अस्थिर बाजार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में इस कृषि संकट के चलते किसानों की आत्महत्या की घटनाएं 1970 से ही प्रारंभ हो गई थीं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 1995 से 2014 के बीच 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की। 2014 से 2022 के बीच नौ वर्षों में यह संख्या 10,047 थी। नाबार्ड के अनुसार मौजूदा समय देश के सभी तरह के बैंकों का करीब 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यानी प्रति किसान कर्ज 1.35 लाख रुपये है।

पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि में बदलाव के साथ किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उनसे वार्ता की भी जरूरत जताई। कृषि पर संसदीय मामलों की कमेटी ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी की सिफारिश की है। संसद के पटल पर रखी गई इस रपट में पीएम किसान सम्मान राशि को भी 6,000 से 12,000 रुपये करने की भी संस्तुति है। इसी बीच अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण सरकारों की चिंता बढ़ रही है। 2020 में मोदी सरकार द्वारा तीन कृषि कानून लाने और फिर इन्हें खत्म करने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून के अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। कोई भी लाइसेंस धारक व्यापारी किसानों से सहमत कीमतों पर उपज खरीद सकता था। कृषि उत्पादकों का यह व्यापार राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मंडी कर से मुक्त किया गया था। किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून किसानों से अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देने के लिए था। इसके तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं, बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों द्वारा की जाती। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टाक सीमा हटा ली गई थी। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार किसानों को जरूरी दर से कम एमएसपी देने से किसानों को लगभग 60 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके चलते किसान कर्ज में डूब गए हैं। यह किसानों की आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। इसी असंतोष के चलते 2020 में किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ किसानों की मांगों पर सहमति बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही। कई दौर की मीटिंग के बाद भी आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट का अता-पता नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पांच सदस्यीय कमेटी के कुछ निष्कर्ष अवश्य प्रकाश में आए हैं, जिसके अनुसार किसानों की लागत और कृषि हेतु लिए गए कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। समिति ने उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए एमएसपी को कानूनी मान्यता सहित 11 मुद्दे चिह्नित किए हैं। हाल में कृषि उत्पादकता में गिरावट, बढ़ती कृषि लागत, अपर्याप्त मार्केटिंग सिस्टम और सिकुड़ते कृषि रोजगार से कृषि आय में गिरावट आई है। घटता जलस्तर, बार-बार सूखा पड़ना, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा का पैटर्न, भीषण गर्मी आदि जलवायु आपदाएं भी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। किसान अपनी आजीविका को बनाए रखने से संबंधित चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसी आर्थिक असुरक्षा के चलते पंजाब के किसान संगठनों ने स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार सभी फसलों पर एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एमएसपी को महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाना है। यह प्रणाली पांच दशकों से अधिक समय से चल रही है।

सरकार की धारणा है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने से उसे सभी कृषि उपज खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, लेकिन इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, सभी कृषि उपज बाजार में नहीं आतीं। किसान कुछ उपज को स्वयं के उपभोग, बीज और पशु चारे के लिए बचाकर रखते हैं। दूसरा, सरकारी हस्तक्षेप केवल तभी तक आवश्यक होता है, जब किसी वस्तु का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है। इसीलिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू करने पर विचार होना चाहिए। एमएसपी की गारंटी न केवल किसानों की आत्महत्या को रोकने और महंगाई घटाने में सहायक होगी, बल्कि जल संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति को संरक्षित करने में भी मददगार होगी।

इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, सभी कृषि उपज बाजार में नहीं आतीं। किसान कुछ उपज को स्वयं के उपभोग, बीज और पशु चारे के लिए बचाकर रखते हैं। दूसरा, सरकारी हस्तक्षेप केवल तभी तक आवश्यक होता है, जब किसी वस्तु का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है। इसीलिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू करने पर विचार होना चाहिए। एमएसपी की गारंटी न केवल किसानों की आत्महत्या को रोकने और महंगाई घटाने में सहायक होगी, बल्कि जल संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति को संरक्षित करने में भी मददगार होगी।

संजय वर्मा 'दृष्टि' को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 सम्मान

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य मंच नई दिल्ली राष्ट्रीय हिन्दी इटसेल्फ मंच सारा सच प्रतिवर्ष देश और प्रदेश की विशिष्ठ प्रतिभाओं को राष्ट्रीय प्रतिभा उपलब्धि अवॉर्ड 2021से सम्मानित करता आरहा है नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया पर सर्वे अनुसार चीफ एडिटर सारा सच (राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र),दिल्ली वार्ता(राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका), को फाउंडर हिंदी वाणी(हिंदी मासिक पत्रिका) कंस्ट्रक्शन क्लब ऑफ इंडिया रफी मार्ग नईदिल्ली की और से चीफ ऐडमिरर इन चीफ सलीम अहमद सिद्दकी के द्धारा मनावर जिला धार मप्र के संजय वर्माश्दृष्टिश् को राष्ट्रीय हिंदी साहित्य की और से योर पेन योर वॉइस साहित्य लेखन क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन एवं निरन्तर साहित्य सेवा हेतु मंच राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 सम्मान से विभूषित किया जाकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की ।संजय वर्माश्दृष्टिश् की देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं 50 वर्षो से निरन्तर प्रकाशित होती रहती है।अबतक 617सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड में तीन बार अलग - अलग विधा में दर्ज है` स्टार बुक रिकार्ड से भी सम्मानित है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com